ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/324167853

□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□

Research · November 2016

CITATIONS
0

READS
9

1 author:

Bhagawati Paraksh Sharma
Pacific University India
268 PUBLICATIONS **0** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Bhagawati Paraksh Sharma on 03 April 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

चीन की चुनौतियाँ और समाधान

भगवती प्रकाश

स्वदेशी जागरण मंच

'धर्म क्षेत्र', शिवशक्ति मंदिर, रामकृष्णपुरम्, सेक्टर 8
नई दिल्ली – 110022

लेखक की अन्य कृतियां

1. स्वदेशी
2. आर्थिक वैश्वीकरण : बाहरी दबाव जन्य रीतिनीति
3. आर्थिक वैश्वीकरण : वैश्विक षडयन्त्र की रीतिनीति
4. स्वदेशी का शंखनाद
5. विश्व व्यापार संगठन
6. वैश्विक आर्थिक संकट : कारण व समाधान
7. Dis - Investment
8. चीन एक सुरक्षा संकट
9. Reasons of Global Meltdown & Lessons for India
10. फुटकर व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश
11. FDI in Insurance
12. Chinese Agression
13. विकास की भारतीय अवधारण
14. Nuclear Programme of India
15. मेड बाई इंडिया
16. एकात्म मानव दर्शन
17. Solar Power Need for
18. सौर ऊर्जा – तकनीकी राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता

मूल्य : रूपये 10/–

भूमिका

देश के लिए चीन से बढ़ रहा सुरक्षा संकट व उसकी बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियां अत्यंत चिंताजनक हैं। चीन से बढ़ रहे सुरक्षा संकट और देश में चीनी वस्तुओं की उत्तरोत्तर बढ़ रही बिक्री के साथ ही भारत सरकार द्वारा चीन को प्रदान की जाती रही उत्तरोत्तर अधिकाधिक व्यापार व निवेश की विविध सुविधाओं से चीन के बढ़ते आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति देश का प्रत्येक सजग नागरिक अत्यन्त चिन्तित है। **चीन की हाल की ताजा घुसपैठों एवं हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी का जल अवरूद्ध कर लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रस्तावों पर वीटो का उपयोग और आणविक आपूर्ति समूह में भारत के प्रवेश का विरोध आदि सभी घोर शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां हैं।**

चीन ने 1962 में ही भारत पर आक्रमण करके अक्सई चिन में भारत की 38,000 वर्ग किमी. भूमि बलात हड़प ली थी। इसके बाद भी विगत 50 वर्षों में वह सीमा पर निरन्तर घुसपैठ करता रहा है और भारतीय सीमा में अनेक नवीन स्थानों पर छुट–पुट अतिक्रमण करता ही जा रहा है। वर्ष 2013 में 14–15 अप्रैल की रात्रि में तो उसने 40–50 सैनिकों के एक प्लाटून व कुछ कुत्तों के बल पर 'दौलत बेग ओल्डी' के, रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र पर 21 दिन तक अपना अधिकार जमा लिया था। तब यू.पी.ए. सरकार ने उन 40–50 घुसपैठियों को सैन्य बलों की सहायता से निकाल बाहर करने के स्थान पर, चीन की अनेक अपमान जनक शर्तें मान कर ही उन्हें वापस जाने पर सहमत किया था। यह निर्णय अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। चीनी राष्ट्रपति शी. जिनपिंग की 2014 के सितम्बर 17–19 की त्रि–दिवसीय यात्रा के दौरान भारत के साथ हस्ताक्षरित 16 सहमति पत्रों जिनमें चीन के 20 अरब डालर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व दो औद्योगिक पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, भी भारत में चीन का आर्थिक प्रभुत्व बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे।

तब सीमा पर इस गम्भीर तनाव की स्थिति में भी, गृह मंत्रालय ने सीमा की रक्षा व प्रबन्ध का कार्य सेना को सौपने से मना कर दिया था जो भी अत्यन्त चिन्ताजनक है। भारत–तिब्बत सीमा पर सीमा की रक्षा व उसका प्रबन्ध चाहे भारत–तिब्बत सीमा पुलिस करे। लेकिन, यह गृह मंत्रालय के नियन्त्रण में नहीं सेना के निर्देशन में होना चाहिये। गृह मंत्रालय द्वारा सीमा रक्षा के सम्बन्ध में इस तरह का गतिरोध उत्पन्न करना कतई उचित नहीं है।

तब इन 40–50 चीनी सैनिकों से ही ब्लेकमेल होकर सरकार द्वारा अपनी सेना को सीमा रेखा से 38 किमी. पीछे हटाने और चुमार क्षेत्र के भारतीय सीमा में स्थित अपने बंकर तोड़ने को सहमत होने जैसी शर्तों पर सरकार का चीन से समझौता भी देश की भावी सुरक्षा के लिये एक गम्भीर चुनौति है। वस्तुतः सरकार को चीनी घुसपैठ के विरूद्ध सीमारक्षण का कार्य सेना को देकर, चीन से आक्रान्त, दौलत बेग ओल्डी के क्षेत्र को मुक्त करने का ही निर्णय लेना चाहिये था।

चीन द्वारा की जा रही इन अनवरत शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के उपरान्त भी, भारत द्वारा चीन को सर्वाधिक व्यापार सुविधाएँ देना और भी आत्मघाती कदम है। देश का सर्वाधिक 51 अरब डालर का व्यापार घाटा, आज केवल चीन के साथ ही है। आवश्यकता इस बात की है कि चीन का जो आज देश में हम 5–6 लाख करोड़ रूपये का माल आयात करते हैं, उसे हमें तत्काल बन्द करना चाहिये। देश की जनता आज चीनी माल खरीदना बन्द कर दे, यह चीन के प्रति हमारा सर्वोत्तम कदम सिद्ध होगा।

आम जनता में आज जो लोग चीनी फर्नीचर, विद्युतीय साज सामान, टेक्सन का चीनी केल्कुलेटर, लीनोवो का कम्प्यूटर, चीनी मोबाइल फोन, बल्ब आदि देश में खरीदते है, उन्हें इसे तत्काल बन्द करना चाहिये। आज चीन का 60 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन निर्यात आधारित है। ऐसे में चीन के द्वारा अपने देश सहित, तिब्बत व अफ्रीका में कई स्थानों पर जो मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है और सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से विश्व के लिये पर्यावरण संकट उत्पन्न किया जा रहा है। इन सबके आधार पर यदि उसके विरूद्ध विश्व समुदाय को भी चीनी माल के बहिष्कार का आवाहन किया जाये तो विश्व के लिये सुरक्षा संकट के रूप में उभर रहे चीन को अच्छा पाठ पढ़ाया जा सकता है। अस्तू, इस हेतु ही यह लघु पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। आशा है पाठकों को पसन्द आयेगी।

इन्हीं चिन्ताओं पर केन्द्रित लेखक की पूर्व में 3 पुस्तकें हिन्दी भाषा में व 1 अंग्रेजी में विविध प्रान्तों में कई बार पुनर्मुद्रित बड़ी संख्या में बिक चुकी हैं। लेखक की ओर से देश हित में इस पुस्तक के यथावत शब्दशः मुद्रण व प्रसार के लिये सब लोग व संगठन स्वतंत्र हैं। ऐसा होने से इस पुस्तक का देश भर में व्यापक प्रसार हो सकेगा।

आशा है कि सभी विद्वान व राष्ट्रनिष्ठ पाठक, इस विषय पर राष्ट्र जागरण हेतु यथेष्ट प्रयास करेंगे।

कार्तिक शुक्ल तृतीया संवत 2073
बुधवार, नवंबर 3, 2016

भगवती प्रकाश
bps992@gmail.com

चीन की बढ़ती शत्रुतापूर्ण गतिविधियाँ

चीन की सभी प्रकार की आर्थिक, सामरिक व कूटनीतिक चुनौतियों का समुचित विवेचन करने वाली लेखक की 4 पुस्तकें – 3 हिन्दी में व 1 अंग्रेजी में 2010–2014 के बीच में प्रकाशित हो चुकी हैं। चीन की ताजा शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों व अब तक की हमारी शिथिलताओं या कमजोरियों को चिन्हित करने वाली यह एक और पुस्तक पाठकों की मांग पर प्रस्तुत की जा रही है। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में चीन की ताजा शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों का विवेचन, द्वितीय अध्याय में चीन से मिल रही आर्थिक चुनौतियों का विवेचन किया गया है, तीसरे में हमारी पिछली गलतियों एवं चौथे अध्याय में अब हमारे लिये करणीय कार्यों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। चीन के द्वारा जिस प्रकार से भारत विरोधी विभिन्न षडयंत्र रचते हुए भारत को हर मोर्चे पर चुनौती दी जा रही है अथवा भारत के हितों को क्षति पहुंचाई जा रही है, इन सबका ज्ञान प्रत्येक भारतीय नागरिक को हो सके की दृष्टि से ही इन सबका अति संक्षिप्त विवेचन इस पुस्तक में किया गया है।

अध्याय 1

चीन की ताजा भारत विरोधी कार्यवाहियां

चीन द्वारा इन विगत 10 वर्षों में अनेक अवसरों पर भारत द्वारा आतंकवादियों के संबंध में लाये प्रस्तावों का संयुक्त राष्ट्र में विरोध, आणविक आपूर्ति समूह में प्रवेश का विरोध, ब्रह्मपुत्र का जल रोकना व आये दिन की घुसपैठ आदि सभी भारत के विरूद्ध घोर शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां हैं। वस्तुतः, चीन में 1949 में साम्यवादी सरकार के बनने के बाद से ही भारत के प्रति वह निरन्तर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता रहा है। आज वह भारत के विरूद्ध आर्थिक, सामरिक, आतंकवादी व कूटनीति प्रेरक द्वेषपूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त हो प्रत्यक्ष व परोक्ष में सब प्रकार से हानि पहुँचाने के कार्य कर रहा है। स्वयं चीन की भारत विरोधी गतिविधियाँ तो चरम पर हैं ही, वह पाकिस्तान को भी हर प्रकार की भारत विरोधी कार्यवाही के लिये सभी वैध व अवैध तरीकों से सहयोग कर रहा है। लेकिन ऐसी सब प्रकार की घोर शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त चीन से प्रति वर्ष 63 अरब डालर (4.25 लाख करोड़ रूपये तुल्य) मूल्य की वस्तुओं का ज्ञात रूप में एवं बड़ी मात्रा में छद्म रूप में बिना बिल या अल्प मूल्य के बिल पर वस्तुएँ जिनका कुल मूल्य 6 लाख करोड़ रूपयों से अधिक है, का आयात कर उसका (चीन का) आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। आज भारत के 27 देशों के साथ कुल 116 अरब डालर के घाटे में सर्वाधिक 53 अरब डालर का अर्थात लगभग आधा घाटा केवल चीन से अंधाधुंध आयात किये जा रहे उत्पादों के कारण है। इसी घाटे के कारण रूपये की कीमत जो 2011 में 50 रूपये प्रति डालर थी वह घट कर आज 67 रूपये प्रति डालर ही रह गयी है। यदि हम केवल चीनी वस्तओं का अंधाधुंध आयात नहीं करते, तो भारतीय रूपये की कीमत आज 50 रूपये ही बनी रहती और देश में जो कई हजार उद्यम बंद हुये एवं एक करोड़ से अधिक श्रमिक बेरोजगार हुए वे नहीं होते। यदि आज भी हमने सचेत हो कर चीन की वस्तुओं का बहिष्कार नहीं किया तो भविष्य में चीन भारत को हर प्रकार से आहत करता रहेगा और देश के उद्योग, व्यापार व वाणिज्य पर गंभीर दुष्प्रभाव होंगे।

चीन का गहराता संकट व उसे करारा उत्तर देने का सर्वोत्तम अवसर

चीन, आज सम्पूर्ण विश्व मानवता के लिये स्थायी शान्ति, मानवाधिकारों की रक्षा, आतंकवाद से मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं सामरिक संतुलन लिये गम्भीर चुनौती बना हुआ है। लेकिन, वह आज एक गम्भीर आर्थिक व वित्तीय ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है। वर्ष 2008 में अमेरिकी 'मेल्ट डाउन' से अधिक भयावह 'मेल्ट डाउन' अर्थात आर्थिक संकट वहाँ मुँह बायें उसे निगलने को खड़ा है। आज वहाँ की कम्पनियाँ 180 खरब डालर अर्थात $18 Trillion (12060 खरब अर्थात 1206 लाख करोड़ रूपये तुल्य) कर्ज में डूबी हुयी है। यह राशि उनके सकल घरेलू उत्पाद की 170 प्रतिशत है। पूरी चीनी अर्थ व्यवस्था आज उसके घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत ऋण के बोझ तले चरमराने को है। चीन के सारे बैंक सहित उसका मुद्रा तंत्र, उद्योग व वाणिज्य सब कुछ डूब सकता है। यदि हमने एक वर्ष तक कोई चीनी उत्पाद क्रय नहीं किया तो, यह होना ही है। यदि हम जो चीनी वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें खरीदना हमने जारी रखा तो चीनी अर्थव्यवस्था इस पूरे संकट से अत्यंत सहजता से पार पा जायेगी। थोड़े समय चीनी माल इसी तरह बिकता रहा तो, चीन ने इस पूरे संकट से पार पाने की योजना की घोषणा भी सोमवार 10 अक्टूबर को कर दी है। अब वह उसकी अकुशल कम्पनियों को अपनी मौत मर जाने देगा और कुशल कंपनियाँ, जिनके उत्पाद विश्व भर में बिकते हैं, उनके ऋण को पूंजी में बदल देगा। कम्पनी को ऋण पर ब्याज चुकाना होता है और किश्त भी प्रतिमाह चुकानी होती है। उस ऋण को पूंजी में बदलते ही (debt-equity swap) कंपनी पर से किश्त व ब्याज के भुगतान का दायित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे में आज की मंदी में कम्पनी अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाने पर भी जीवित रह सकती है, क्योंकि उसे अब न तो किश्त चुकानी है और न ही ब्याज। लेकिन यदि उसकी बिक्री ही नहीं हुयी तो उसे बन्द होना ही है। यदि चीनी माल का हमने पूर्ण बहिष्कार कर दिया और विश्व में भी हम चीन की पर्यावरण, मानवाधिकार, आतंकवाद एवं विश्व शांति के संबंध में खड़ी की जा रही चुनौतियों का स्मरण कराकर सोशल मीडिया पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवाहन करें तो अधिकांश चीनी कंपनियाँ बन्द होगी ही। ऋण को पूंजी में बदलने के बाद भी वे बंद होगी। ऐसे में चीन के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 170 प्रतिशत तक पहुंच चुके कंपनी ऋणों का दो तिहाई अर्थात उसके सकल घरेलू उत्पाद तुल्य 120 खरब डालर ($12 Trillion) के डूबने का डूबना तो निश्चित ही है। चीन में कुल बकाया ऋणों की राशि तो आज 280 खरब डालर अर्थात $ 28 Trillion अर्थात उसके सकल घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। यह राशि अमेरिका व जापान के संयुक्त वाणिज्यिक बैंकिंग तंत्र के तुल्य है। यदि वर्तमान में चीन ने अपनी कंपनी ऋणों की पुनर्रचना जिसमें ऋणों को पूंजी में परिवर्तन करना भी

सम्मिलित है, के सहारे अपने बैंकिंग तंत्र व बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों के उत्पादन तंत्र को बचा लिया तो वह 3–5 वर्ष में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ विश्व की क्रमांक एक की आर्थिक शक्ति व सामरिक शक्ति बन कर खड़ा होगा। दूसरी ओर, अभी जबकि चीन की अधिकांश कंपनियां व सम्पूर्ण बैकिंग तंत्र चरमराने को है, ऐसे में यदि हम चीनी वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे तो उसका उत्पादन तंत्र व बैंकिंग तंत्र ध्वस्त होगा, निर्यात घटेंगे, विदेशी व्यापार में घाटा भी होगा, विदेशी मुद्रा भण्डार चुक जायेंगे और विश्व चैन की सांस लेगा। भारत का निकट पड़ोसी होने से चीन का सबल होना भारत के लिये सर्वाधिक संकट कारक होगा।

आज चीन की सर्वाधिक शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां उसकी भारत के विरूद्ध है। हाल ही में उसने भारत सीमा में अरूणाचल व उत्तराखण्ड में भारत की सीमा में हमारे नहरों आदि के निर्माण को बाधित किया है। वह वर्ष में 300–400 बार सीमा का अतिक्रमण करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के मामलों में भारत के प्रस्तावों के विरूद्ध वीटो का उपयोग कर रहा है। उसने भारत के आणविक आपूर्ति समूह (Nuclear Suppliers Group) में प्रवेश का विरोध किया है। पाक अधिकृत कश्मीर में भारत के विरोध के बाद भी वह व्यापक स्तर पर निर्माण कर वहीं से 46 अरब डालर के चीन–पाक आर्थिक गलियारे का विकास कर रहा है। भारत में जल संकट उत्पन्न करने के लिये ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक रहा है। सिंधु नदी का अतिरिक्त जल हम पाकिस्तान में जाने दें, इसके लिये धमकियां दे रहा है। हाल ही में 3 नवम्बर को उसने अरूणाचल में सीमा से 29 किमी अंदर हमारा नहर निर्माण का कार्य रूकवाने का दुस्साहस किया है।

इस प्रकार चीन का आर्थिक व सामरिक सशक्तिकरण भारत के लिये सर्वाधिक चुनौतिपूर्ण होगा और हमें अपने संसाधन विकास के स्थान पर चीन–पाक से सुरक्षा में लगाने होंगे। इसके लिये भारत के विकास के लिये चीन पर आर्थिक अंकुश सर्वाधिक आवश्यक है। अतएव आज जब चीन एक आर्थिक, वित्तीय, बैंकिंग व कार्पोरेट संकट के ज्वालामुखी पर बैठा है, चीनी वस्तुओं का परित्याग ही इस संकट में विस्फोट की संभावना निश्चित करेगा।

I पाकिस्तान के पक्ष में दबाव बनाने के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जल रोकना

भारत की सेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने की प्रतिक्रिया में एवं सिन्धु नदी जल बँटवारे की भारत द्वारा पुनर्समीक्षा व उसे निरस्त करने की चेतावनी देने के विरूद्ध पाकिस्तान को भारत विरोधी कार्यवाहियों में सम्बल देने की गरज से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जेंग पो के जल को अवरूद्ध कर चीन ने भारत के विरूद्ध बदले की कार्यवाही के रूप में जल संकट उत्पन्न करने की चेतावनी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भारत को अपने पांरपरिक रूप से प्राप्त जल से वंचित करना अवैधानिक है। लेकिन, केवल पाकिस्तान को खुश करने के लिए चीन ने यह भारत विरोधी कदम उठाया है। चीन का प्रत्यक्ष रूप में भारतीय सेना के द्वारा सितम्बर 28–29 की रात को पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के विरूद्ध पाक अधिकृत कश्मीर में की गई 'सर्जिकल' कार्यवाही के विरूद्ध पाकिस्तान के पक्ष में उठाया गया यह भारत विरोधी कदम है। चूंकि भारत ने 1960 के अयूब समझौते के अधीन पाकिस्तान के हिस्से के जल से, पाकिस्तान में अतिरिक्त मात्रा में जा रहे जल को रोकने की चेतावनी दी थी। इसके विरूद्ध भारत तो जब जल रोकेगा तब रोकेगा, पर चीन ने तो पाक समर्थन में यह गैर कानूनी कदम उठा ही लिया है।

वस्तुतः उड़ी में आतंकवादी आक्रमण के बाद भारतीय सेना की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के विरूद्ध शल्य क्रिया जैसी सीमित सैन्य कार्यवाही (Surgical Strikes) के विरोध में पाकिस्तान के प्रति अपनी मित्रता का प्रदर्शन करते हुये चीन ने जेंगबो नामक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी अवरूद्ध कर भारत को परोक्ष में यह चेतवनी दी है कि भारत द्वारा पाकिस्तान के विरूद्ध आतंकवाद विरोधी कार्यवाही करने पर या सिन्धु नदी के जल से पाकिस्तान को वंचित करने पर वह ब्रह्मपुत्र नदी के जल से भारत को वंचित कर देगा। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की उपरोक्त सहायक नदी का पानी रोकने के लिये ही वहाँ एक हाईड्रो प्रोजेक्ट लगा रहा है। भारत के लिए यह भारी चिंता की बात है क्योंकि, चीन के इस कदम से भारत समेत कई देशों में ब्रह्मपुत्र के पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है। इससे भारत की 10 करोड़ से अधिक आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

चीन ने यह काम ऐसे वक्त में किया है जब उड़ी हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सिन्धु जल समझौते से अतिरिक्त पाकिस्तान में जा रहे जल को रोकने हेतु यह बैठक की थी। साथ ही इस समझौते की समीक्षा करने का भी फैसला किया था। भारत ने समीक्षा का यह निर्णय और सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय केवल पाक पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के विरूद्ध दबाव बनाने के लिए किया था। ऐसे में चीन, भारत का जल अवरूद्ध करने वाला यह कदम पाकिस्तान के साथ मिलकर उल्टा भारत पर दबाव बढ़ाने की धमकी के रूप में उपयोग कर रहा है।

पठानकोट व उड़ी में आतंकवादी आक्रमणों के विरूद्ध पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिये ही पाक के साथ हुए सिंधु समझौते पर मोदी बोले थे कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। भारत–पाक के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। उड़ी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर हर तरफ से दबाव बनाने की कोशिश के क्रम में ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिंधु जल समझौते पर रिव्यू मीटिंग की थी। इसमें विदेश सचिव एस जयशंकर नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और पीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र शामिल थे। 1960 के सिंधु जल समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को भारत से बहने वाली छः नदियों का पानी मिलता है। इसी पानी से पाकिस्तान में कई प्राजेक्ट चल रहे हैं और सिंचाई की जा रही है। लेकिन भारत द्वारा अपने हिस्से के जल का पूरा उपयोग नहीं कर पाने से ही पाकिस्तान को अतिरिक्त पानी मिल रहा है। इसलिये प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हुई मीटिंग में यह फैसला हुआ कि भारत झेलम सहित पाक के हिस्से में बहने वाली नदियों के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार भारत सिंधु जल समझौते के अधीन पश्चिमी नदियों के पानी से 18 हजार मेघावाट बिजली बना सकता है। नेहरू – अयूब समझौते के अधीन भारत के अधिकारों की पहचान करने के लिए एक इंटर मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स बनाने का भी निर्णय लिया गया था। अधिकारियों ने यह भी कहा कि तुलबुल प्रोजेक्ट का भी रिव्यू किया जाएगा जिस पर 2007 में काम बंद हो गया था। भारत ने इस नेहरू–अयूब समझौते को निरस्त करने तक की धमकी भी दे दी थी।

इस समझौते के तहत छः नदियों – व्यास, रावी, सतलज सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी भारत और पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा कि भारत उसे समझौते की शर्तों से कम पानी देता है। वह दो बार इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में शिकायत भी कर चुका है। समझौते के अनुसार सतलज, व्यास और रावी का अधिकांश पानी भारत के हिस्से में रखा गया था। जब कि सिंधु, झेलम और चिनाब अधिकांश पानी पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया था। यदि यह समझौता कैंसल हुआ तो प्यासा रह जाएगा पाकिस्तान। सिंधु और बाकी पांच नदियां पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से की प्यास बुझाती है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून ने भी पिछले दिनों कहा था कि सिंधु के पानी के बगैर देश का एक हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा। सिंधु, झेलम और चिनाब में वाटर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली की वैसे ही भारी परेशानी है। अगर यह समझौता कैंसल हो गया तो पाकिस्तान में बिजली संकट भी खड़ा हो सकता है। इसके अलावा, इन तीनों नदियों से एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई भी की जाती है। इसलिये इसकी संवेदनशीलता व गम्भीरता को दखते हुये ही पाकिस्तान को बल देने के लिये चीन ने पाकिस्तान की ओर से यह बदले की कार्यवाही करने जैसा कदम उठाया। ब्रह्मपुत्र नदी के जल को रोकने का काम चीन में 2008 से ही चल रहा है। लेकिन अभी जेंग पो नदी का पानी रोककर एक नयी चेतावनी दी है।

तिब्बत में यारलुंग जेंगबो नाम से जानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र की इस सहायक नदी पर चीन ने इस प्रोजेक्ट पर करीब 75 करोड़ डॉलर (5100 करोड़ रूपये तुल्य) का निवेश केवल इसलिये किया है कि वह पाकिस्तान से अपनी मित्रता दृढ़ करने हेतु भारत को क्षति पहुंचा कर दण्डित करे। चीन का यह प्रोजेक्ट तिब्बत के जाइगस क्षेत्र में है, जो सिक्किम के निकट पड़ता है। वस्तुतः जाइगस से ही ब्रह्मपुत्र नदी अरूणाचल प्रदेश में बहते हुए प्रवेश करती है। इसलिये यहाँ बांध बना कर भारत का सर्वाधिक पानी रोक भी सकता है और जब चाहे तो जल प्लावन करके वहाँ कृत्रिम बाढ़ का प्रकोप भी पैदा कर दे। पूर्व में 2000, 2001 और 2005 में चीन, हिमाचल में अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ कर बाढ़ का संकट पैदा कर चुका है। चीन द्वारा 2000 में अचानक सतलज के बेसिन में बिना किसी पूर्व सूचना के पानी छोड़ने से हिमाचल में बाढ़ का संकट पैदा होने से 100 लोग मारे गये थे। 2000 के मध्य में अरूणाचल में भी अचानक बिना पूर्व सूचना के ब्रह्मपुत्र में बाँधों का पानी छोड़ देने से ब्रह्मपुत्र का जल स्तर 30 मीटर चढ़ गया, जिसमें अरूणाचल में 26 लोग मारे गये व 35,000 लोग बेघर हो गये। भारत में प्रवेश के पूर्व ब्रह्मपुत्र के तिब्बत के ऊपरी भाग के प्रवाह में जल स्तर चढ़ने के समाचारों को भी उसने वहाँ के संचार माध्यमों में आने से भी केवल इस कारण रोक दिया, ताकि भारत को उस कृत्रिम बाढ़ की अग्रिम सूचना न हो सके। हिमाचल में बाढ़ का संकट खड़ा करने के लिये ही छोड़ा था, जिसकी उसने भारत को कोई अग्रिम सूचना नहीं दी। दूसरी ओर पाकिस्तान व बांग्ला देश में, भारत से जाने वाली नदियों में जब भी जल स्तर बढ़ता है तो भारत उसकी हाइड्रोलॉजिकल सूचनायें तत्काल उन्हें देता है। इस प्रकार चीन भारत के विरूद्ध यह नये प्रकार के युद्ध की तैयारी कर रहा है। इन बाँधों के निर्माण से वह भारत के विरूद्ध बनावटी अकाल व बाढ़ के द्वारा आक्रमण कर सकेगा।

चीन अपने इस अत्यन्त महंगे प्रोजेक्ट को 2019 में पूरा कर लेना चाहता है। यह पानी रोकने से भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में ब्रह्मपुत्र के बहाव पर भी व्यापक असर पड़ेगा। पिछले वर्ष भी चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र में डेढ़ अरब डालर की लागत वाला सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस पर भी भारत ने चिंता जताई थी। लेकिन, चीन ने इसकी अनदेखी कर दी है। चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना से इस बात के संकेत मिलते हैं कि तिब्बत के स्वायत क्षेत्र में चीन 3 और जल विद्युत परियोजनायें (हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट) केवल भारत का जल हड़पने के लिये लाने वाला है। इससे सम्पूर्ण पूर्वोत्तर में गम्भीर जल संकट पैदा होगा और चीन इन बांधों का पानी कभी भी छोड़कर पूर्वोत्तर में जलप्लावन का संकट खड़ा कर सकेगा। आज चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मोड़ने की कोशिश केवल इसलिये कर पा रहा है, क्योंकि 1951 में चीन को तिब्बत को हड़प लेने में भारत ने सहयोग किया था। ब्रह्मपुत्र सहित तिब्बत से 10 बड़ी नदियाँ निकलती हैं और जिनसे 11 देशों को जलापूर्त्ति होती है, चीन उन नदियों के जल को मन चाहे ढंग से मोड़ रहा है। यदि जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में समझौता करा कर तिब्बत पर चीन को अधिकार करने में सहयोग नहीं दिया होता और वह स्ततंत्र देश बना रहता तो यह जल संकट ही नहीं उपजता। उत्तर पूर्वी चीन में जलापूर्त्ति के लिये उसका तीन घाटियों वाला बांध पहले से ही है तब भी वह बड़ी मात्रा में जल को तिब्बत से उल्टी दिशा में इसलिये मोड़ रहा है, ताकि वह उधर से भारत का पानी रोक सके। इस हेतु उसने ब्रह्मपुत्र नदी को व्यापक स्तर पर अवरूद्ध करने के लिए अनेक बांध बनाने शुरू कर दिये हैं। उन बांधो से उसने सुरंगों (टनल), पाईप लाईनों और नहरों का निर्माण शुरू कर दिया है। उपग्रहों के चित्रों, अन्तर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों, अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं व चीनी समाचार पत्रों के अनुसार वहाँ व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। स्मरण रहे, मेकॉन्ग नाम की नदी भी वहीं तिब्बत से निकलती है जिससे लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम और थाइलैण्ड इन चार देशों को जलापूर्त्ति होती रही है। उसके प्रवाह को चीन ने अवरूद्ध किया है। वहाँ उन देशों में बड़ी मात्रा में भू–भाग सूखे में बदल रहा है क्योंकि चीन ने मेकॉन्ग नदी का पानी रोक दिया है। इसी विवाद के चलते पाँच देशों का मेकान्ग नदी आयोग बना हुआ है, चीन या तो उसकी बैठकों में जाता नहीं है और जाता है तो कहता है कि हमने तो आपका कोई पानी नहीं रोका है, कोई डाईवर्जन नहीं किया है। चीन इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है कि उसने इन देशों का जल प्रवाह रोका है, जबकि ये चार देश बहुत परेशान हैं। आज जब हमारे देश के 10 करोड़ लोगों का जीवन ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर है, हमको इस विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद के रूप में उठाना चाहिये। ब्रह्मपुत्र का जल अवरूद्ध होने से बांग्ला देश भी प्रभावित होगा। इसलिये हमें उसे भी साथ लेना चाहिये। चीन को इस बात के लिए बाध्य करना चाहिये तथा उसकी प्रतिबद्धता लेनी चाहिये कि वह ब्रह्मपुत्र के जल को मोड़े नहीं (डाईवर्ट नहीं करे)। अन्यथा अरूणाचल प्रदेश और असम सूखे में बदल जायेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी में सवा लाख क्यूबिक फीट पानी प्रति सैकण्ड बहता है, ग्लेशियरों का एकदम विशुद्ध जल। बाढ़ के समय तो 10 लाख क्यूबिक फीट पानी उसमें प्रति सैकंड बहता है। ब्रह्मपुत्र को मोड़ देने से सारी जल राशि हमको मिलनी बन्द हो जायेगी और स्थिति यह हो जायेगी कि ब्रह्मपुत्र नदी मौसमी नाले में बदल सकती है।

II भारत में आंतकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान व पाक आंतकियों को सर्मथन

चीन लगभग 10 वर्षों से निरंतर भारत द्वारा विविध जेहादी आंतकवादी संगठनों व आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में लाए गए प्रस्तावों का विरोध करता रहा है। हाल ही में ताजा घटनाक्रम के अधीन अक्टोबर 1 को पाकिस्तान के

लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी, मौलाना मसूद अजहर जिसने जेश–ए–मोहम्मद आतंकवादी संगठन की स्थापना की थी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव का चीन ने अकारण पुनः विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में निरन्तर व अकारण विरोध व वीटो वह केवल भारत को अपमानित व आहत करने व कूटनीतिक पराजय का अनुभव कराने के लिये कर रहा है। वह केवल भारत में हिंसा व जेहादी आतंक फैलाने के दोषी आतंकवादी संगठनों व आतंकवादियों को बढ़ावा देने और पाकिस्तान को भारत में आतंक व हिंसा फैलाने में सहयोग देने हेतु ही चीन, संयुक्त राष्ट्र संघ में विगत 10 वर्षों में अनेक बार भारत के प्रस्तावों का विरोध व उस पर वीटो करता रहा है। इस प्रकार के भारत विरोधी और भारत के विरूद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देने हेतु चीन द्वारा वीटो किये जाने के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से कुछ अग्रलिखित हैं

1. **मौलाना मसूद अजहर के बचाव में भारत के प्रस्ताव पर अनेक बार वीटो** : मौलाना मसूद अजहर एक खतरनाक आतंकवादी है। 1990 में एअर इण्डिया का विमान अपहरण हो जाने पर भारत की उसे विमान के कन्धार में बन्धक बनाये यात्रियों को आतंकवादियों के चुंगुल से बचाने के बदले में छोड़ना पड़ा था। वह लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी रहा है। उसने ही 'जैश ए मोहम्मद' नामक आतंकी संगठन बनाया था। वर्ष 2009 से भारत द्वारा बार–बार उसे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर प्रत्येक बार चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो किया है। पठानकोट आक्रमण के बाद भारत द्वारा हाल ही में मार्च 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्ताव क्रमांक 1267 के अधीन एक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने का नये सिरे से पुनः आवेदन किया था उस पर मार्च 31 को चीन ने वीटो का उपयोग कर उसे अवरूद्ध कर दिया था। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से अकेले चीन भारत को आहत व अपमानित करने के लिए भारत के प्रस्ताव के विरूद्ध बार–बार वीटो करता रहा है। इसी क्रम में अभी अक्टोबर 1, 2016 को जब हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो 'चीनी दिवस 1 अक्टोबर' पर चीन व उसके नागरिकों की मंगल कामना करते हुये उनकी चतुर्विध प्रगति का सन्देश दिया उसी दिन चीन ने एक बार फिर जैश–ए–मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने से बचा लिया। उसने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रस्ताव को फिर से वीटो कर दिया। चीन की ओर से मार्च 2016 में लगाए गए वीटो की समय सीमा सोमवार को खत्म हो रही थी और अगर चीन ने फिर से वीटो नहीं किया होता तो भारत का प्रस्ताव स्वतः पारित हो गया होता।

   अब चीन की यह रोक अगले छः महीने के लिए फिर बढ़ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, ''भारत की ओर से मार्च, 2016 में 1,267 समिति को सौंपे गये आवेदन पर तकनीकी रोक को पहले ही आगे बढ़ा दिया गया है।'' उन्होंने कहा, 'भारत के आवेदन पर अब भी मतभेद हैं। तकनीकी रोक के आगे बढ़ जाने के बाद समिति को इस मामले पर विचार करने और संबंधित पक्षों को आगे विचार–विमर्श के लिए समय मिल जाएगा। इसी साल 31 मार्च को भी चीन ने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड इसी मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कराने के कदम पर रोक लगा दी थी। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होने की वजह से चीन को यह वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में चीन ही इकलौता देश रहा जिसने भारत के आवेदन का विरोध किया, जबकि 14 अन्य देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया।

   यदि ''संयुक्त राष्ट्र 1,267 समिति'' की सूची में अजहर का नाम शामिल हो जाये तो उसकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी और उसकी यात्राओं पर भी रोक लग जाएगी। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की '1,267 समिति' ही आतंकवादियों और आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है। अक्टूबर 1999 में सुरक्षा परिषद ने ही यह 1,267 रेजॉलूशन पास किया था जिसके अधीन ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी घोषित कर उसके और अलकायदा पर प्रतिबंध लगाया था।

   अर्थात अक्टूबर 1, 2016 को उसने छठी बार भारत के विरूद्ध वीटो करने की अवधि बढ़ाने जैसा कदम उठाया है। इसके भी दो दिन बाद ही चीन ने जले पर नमक छिड़ते हुए भारत पर उल्टा यह आरोप जड़ दिया कि भारत आतंकरोधी अभियान के नाम पर अपने राजनैतिक फायदे निकाल रहा है। मौलाना मसूद अजहर के मामले में एक ही वर्ष में दूसरी बार वीटो करके चीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह घोर भारत विरोधी और एक प्रबल पाकिस्तान परस्त देश है।

   अपनी पाकिस्तान परस्ती और भारत विरोधी रूख को सुदृढ़ता ही नहीं, निर्लज्जता पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए ही चीनी विदेश मंत्रालय ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पाकिस्तान को एक अन्तर्राष्ट्रीय आतंक प्रायोजक देश के रूप में सन्दर्भित करने के कथन में विरूद्ध तो चेतावनी ही दे डाली कि भारत पाकिस्तान को 'आतंकवाद की मां' कहने से बाज आये। गोवा में हुये ब्रिक्स समूह के 5 देशों के सम्मेलन में भारत द्वारा पाकिस्तान को 'आतंकवाद को जननी' कहा गया था। उस पर चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ''हुवा चुनयिंग'' ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया की चीन किसी भी देश के समुदाय था सांस्कृतिक समूह को आतंकवाद से जोड़ने के विरूद्ध है। उसने यहाँ तक भी कह दिया कि भारत–पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के बराबर के शिकार है और विश्व समुदाय द्वारा पाकिस्तान के आतंकनिरोधी कदमों व त्याग का समान किया जाना चाहिए।

2. **लखवी के मामले में वीटो** : ताज होटल के हमलावर लखवी की जमानत के मामले में भी चीन ने वीटो का उपयोग किया था। भारत के विरूद्ध मुम्बई में 2008 में ताज होटल पर हमले के प्रायोजक रहमान लखवी की पाकिस्तान में जेल से रिहाई के विरूद्ध भारत द्वारा लाये प्रस्ताव का चीन ने अकारण विरोध कर दिया। वर्ष 2008 में मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले में 166 लोग मारे गये थे। इस हमले का सरगना, उसके विरूद्ध पाये गये प्रमाणों के आधार पर पाकिस्तान के सड़ियाला जेल में बन्द था। लेकिन, उसे अप्रेल 10, 2015 को जेल से रिहा कर दिया गया। इस पर भारत ने पाकिस्तान से इस बात पर सवाल कर लिया कि लखवी घोषित आतंकवादी है जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव क्रमांक 1267 के अधीन प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। ऐसे में उसको जमानत की राशि कहाँ से आई? लखवी ने जमानत के लिए 5 लाख रूपये कैसे चुकाये? उसकी जमानत के लिए दो मुचलकों पर भी 10–10 लाख रूपये जमा किये गये थे। भारत सरकार ने कूटनीतिक नोट के जरीये यह भी जाना चाहा कि यह सारी

राशि किसने चुकाई है? भारतीय खुफिया एजेन्सी रॉ के अनुसार यह राशि आईएसआई द्वारा चुकाई गई थी। इसलिये भारत के संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधी अशोक मुखर्जी ने मई 3, 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की ''प्रस्ताव 1267 समिति'' से इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1267 के अधीन प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही लखवी की सारी सम्पत्ति व धन जब्त किया जा चुका था। ऐसे में यह 25 लाख रूपये की राशि कहां से आई इसके जाँच करने का आग्रह किया था। भारत द्वारा इस संपूर्ण प्रकरण की जांच की मांग पर भी चीन ने जून 25, 2016 को वीटो कर दिया। वीटो का उपयोग कर इसे टेक्नीकल होल्ड पर रखवा दिया।

3. **जमात उद दावा, लश्कर ऐ तैयबा व अल अख्तर ट्रस्ट के मामलों में वीटो** : भारत द्वारा जब भी किसी आतंकवादी या आतंकी संगठन के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 के अधीन प्रस्ताव लाया गया तब केवल 2008 के मुम्बई आक्रमण के अत्यंत वीभत्स मामले को छोड़ कर चीन ने प्रत्येक बार वीटो किया है। मुम्बई आक्रमण में 166 लोगों की मृत्यु व सम्पूर्ण विश्व में इसकी निंदा के कारण चीन ने जमात उल दावा, हाफिज सईद और लखवी को आतंकवादी घोषित किये जाने के मामले में इस मुम्बई आक्रमण के बाद 1267 के अधीन लाये प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया था। स्मरण रहे कि जमात उद दावा को आतंकी संगठन घोषित करने के प्रस्ताव पर इसके पूर्व चीन 3 बार वीटो कर चुका था। चीन ने लश्कर ए तैयबा व जैश ए मोहम्मद के अगुआ संगठन अल अख्तर ट्रस्ट पर प्रतिबन्ध के भारत के प्रस्ताव को भी, भारत पर यह आरोप लगा कर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अवरूद्ध कर दिया कि भारत पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

4. वर्ष 2010 में भी जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर और लश्कर के आतंकी अब्दुर रहमान मक्की व आजम चीमा पर प्रतिबन्ध के प्रस्ताव पर भी चीन ने पुनः वीटो का उपयोग किया था। इस प्रकार 2016 में मसूद अजहर के मामले में वह लम्बे समय से वीटो उपयोग कर रहा है।

5. वर्ष 2015 के प्रारम्भ में ही चीन ने हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन को आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव पर भी वीटो किया था।

भारत का अवमाननाकारक उपहास

मई माह में भारत के प्रधान मंत्री की मई 2015 में चीन यात्रा के दौना दोनों देशों (भारत व चीन) ने आतंकवाद के विरूद्ध मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता अभिव्यक्तकरने वाला संयुक्त वक्तव्य जारी कर सब देशों व संगठनों से आतंकवादियों के जाल को नष्ट करने उनके वित्तीय व देशों के बीच सीमा पार आने जाने पर पूर्ण रोक का आवाहन किया था। उसके अगले ही महीने जून में लखवी के मामले में और उसके ठीक पहले मार्च में मसूद अजहर व पुनः अक्टूबर 1 को भी मसूद अजहर के मामले में वीटो किया। यह अक्टूबर 1 का वीटो तो ठीक उसी दिन किया जिस दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन दिवस पर चीन की सरकार व चीन की जनता को अभिनन्दन संदेश दिया। प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं का उपहास ही उड़ाया है।

ये सभी आतंकवादी न तो चीन के नागरिक है, न उनके संगठन चीन में स्थित हैं और न ही इनका चीन से कोई संबंध है। केवल भारत के विरूद्ध आतंकवाद, उत्तरोत्तर अधिकाधिक बलवान बने और पाकिस्तान को भारत के विरूद्ध आतंकी लड़ाई जारी रखने में कठिनाई नहीं हो, इसलिये ही वह बार–बार वीटो कर रहा है। वीटो के साथ उसने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान को गोवा में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के समय आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की चेतावनी तक दे दी। इससे अधिक शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्या हो सकता है।

III घुसपैठ व बार–बार सीमा का अतिक्रमण कर सामरिक घेराबन्दी

चीन द्वारा निरन्तर एवं बार–बार घुसपैठ के माध्यम से उत्तरोत्तर नये–नये क्षेत्रों में भारतीय भू–भाग पर अनवरत अतिक्रमण, जल व थल सीमा पर चारों ओर से अमित्रतापूर्ण घेराबन्दी, वायु सीमा का आये दिन अतिक्रमण, हमारे दक्षिणी तटीय क्षेत्र में उसका दबदबा बढ़ाने के लिये और वियतनाम में तेल खोज से दूर रहने की चेतावनी देने के उद्देश्य से श्रीलंका के बन्दरगाहों पर अकारण आणविक पनडुब्बियों की कवायद आदि जैसी अनगिनत शत्रुवत कार्यवाहियाँ जारी हैं। तथापि, हमारे द्वारा चीन को अनवरत व बिना किसी पारस्परिक आर्थिक प्रति–लाभ के व्यापार व निवेश की सुविधाएँ देते चले जाने की नीति आत्महीन समर्पण से कम नहीं है। चीन के साथ हमारे विवादों की सूची अत्यन्त लम्बी है। चीन के 1962 में अक्सई चिन के 38,000 भू–भाग को आक्रमण करके हस्तगत कर लिया था, जो पूरे स्विट्जरलेंड के 41,000 वर्ग किमी. के लगभग बराबर एवं इजरायल के क्षेत्रफल से कहीं अधिक है। इसके अतिरिक्त पाक अधिकृत जम्मू–कश्मीर का 5180 वर्ग किमी. भारतीय भू–भाग को उसने पाकिस्तान से ले लिया था। शेष पाक अधिकृत कश्मीर सैन्य उपस्थिति के साथ निर्माण कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त चीन 90,000 वर्ग किमी. भू–भाग पर अपना और दावा जता कर वहाँ बार–बार घुसपैठ कर छुट–पुट नये क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा है। सीमावर्ती गाँवों एवं चारागाहों में बार–बार चीनी सेना वहाँ के स्थानीय गाँववासियों को आतंकित कर वहाँ से पलायन को बाध्य कर रही है। जम्मू–कश्मीर को भारत का अंग नहीं मान कर वहाँ के निवासियों को वीजा प्रदान करने के मामले में उनके भारतीय पासपोर्ट पर वीजा अंकित करने के स्थान पर अलग कागज पर वीजा देकर उसे स्टेपल कर रहा है। अरूणाचल के नागरिकों को वीजा देने से इन्कार कर अरूणाचल को चीनी क्षेत्र ठहरा कर उन्हें बिना वीजा चीन में प्रवेश करने का आग्रह कर रहा है। सितम्बर के मध्य में जम्मू–कश्मीर के डेमचोक में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर हमारी सेना से उसकी सेना का आमने–सामने होना, चुमार में निरन्तर घुसपैठ, वहाँ के नागरिकों की हंटर व बैंतों से पिटाई कर उन्हें क्षेत्र से पलायन को बाध्य करना।

चीनी घुसपैठ की आवृत्ति व अतिक्रमण का क्षेत्र निरन्तर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2008 तक उसकी घुसपैठ की घटनायें 100–147 तक रही हैं, 2011 तक 200 व 2013 से 400 से अधिक हो गयी हैं। सर्वाधिक आश्चर्यजनक है कि चीनी राष्ट्रपति शी. जिनपिंग की 3 दिन की भारत यात्रा व हमारे प्रधानमंत्री के साथ वार्ताओं के दौर में भी भारत पर दबाव लाने के लिये अत्यधिक दबावकारी घुसपैठ चीनी सैनिकों ने की थी। वह घुसपैठ और सैन्य

गतिरोध शी.जिनपिंग के लौट जाने के बाद पूरा सितम्बर माह बीतने पर ही समाप्त हुआ और दोनों ओर के सैनिक नियन्त्रण रेखा से पीछे अपने–अपने क्षेत्र में लौटे। सम्भवतः चीनी घुसपैठ उनके राष्ट्रपति की सौदाकारी क्षमता बढ़ाने व दबाव पूर्वक भारत में अधिकतम निवेश व व्यापार सुविधायें पाने के लिये ही की गयी भी हो तो आश्चर्य नहीं। चीन भारत के साथ होने वाली किसी भी उच्च स्तरीय वार्ता के दौर में यह करता रहा है। ऐसे में भारत के लिये अपना रोष प्रकट करने की दृष्टि से ऐसी वार्ताओं के दौर की रणनीति अपनाने का भी प्रयोग करना चाहिये, जब तक कि चीन घुसपैठ समाप्त न कर लेवें। चीन ऐसी घुसपैठ से हमारे धैर्य व सहनशीलता का ही परीक्षण करता है। ऐसे में हमको चीन को किसी प्रकार की नवीन आर्थिक सुविधाओं को देने से ही इन्कार करने पर न रुक कर चीनी आयातों को भी स्थगित करके अपने तेवल दिखलाने की रणनीति का भी परिचय देना चाहिये। हम आज चीनी वस्तुओं के लिये साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक का बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। व चीनी कम्पनियाँ 3 लाख 72 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर भारत में काम कर रही हैं। चीनी कम्पनियों द्वारा बिलों में कम राशि या बिना बिल का जो चीनी माल बिक रहा है, वह अलग हैं। ऐसे में भारत द्वारा चीन से सभी प्रकार के व्यापार व निवेश सम्बन्ध स्थगित करने का दबाव अधिक श्रेयस्कर होगा। चीनी सैन्य व घुसपैठ के दबाव के आगे उसको अधिकाधिक व्यापार व निवेश सुविधाओं के उपहार देना यू.पी.ए. सरकार की परंपराओं से चीन को अधिक सैन्य दबाव बनाने व घुसपैठ व अतिक्रमण करने का अवसर देगी।

वस्तुतः चीन जब तक, उसके द्वारा किये जा रहे 400 से अधिक वार्षिक अतिक्रमण बन्द न करे तो भारत सरकार को उसे भारत में प्रदान की गयी व्यापार व निवेश सुविधायें निलम्बित कर देनी चाहिये। हाल ही में जो 16 सहमति पत्र चीन के साथ हमने हस्ताक्षरित किये हैं, उनमें देश में रेलों के आधुनिकीकरण से लेकर प्रत्यक्ष निवेश आदि की जो सुविधायें हम देने वाले हैं। उनकी भी हमारे राष्ट्रीय आर्थिक हितों पर होने वाले प्रभावों की दृष्टि से भी समीक्षा भी अनिवार्य है। द्रुतगामी रेलों से सम्बन्धित आज जो साज–सामान चीन से आयेंगे, उनका उत्पादन वहां होने पर रोजगार सृजन वहीं होगा, प्रौद्योगिकी समुन्नयन उनके वहाँ होगा, कम्पोनेन्ट निर्माता सहायक उद्योग उनके ही विकसित होंगे। जबकि यदि ये साज–सामान हम विकसित करेंगे तो इससे देश का रेल सम्बन्धी उत्पादन तंत्र व प्रौद्योगिकी विकसित होगी और उन साज–सामानों का मूल्य व उन पर अर्जित लाभ देश से बाहर चीन के हाथ नहीं लगेगा। आज सामान्य उपभोक्ता के रूप में भी जो भारतवासी कम्प्यूटर लीनोवो, जियोनी या मोटो स्मार्टफोन, टी.एस. एल के टी.वी., टेक्सन के केल्कुलेटर, जेड.टी.ई. या हुवाई के सामान और पेन से लेकर बड़े विद्युतीय यन्त्र आदि खरीदते है, उन्हें बन्द कर दें तो भी देश के हजारो करोड़ रूपये बचेंगे। इसलिये चीन द्वारा हाल ही में निरंतर किए जा रहे सीमा के अतिक्रमणों को देखते हुए देश वासियों को चीन के उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए। चीन ने इतने बड़े भारत जैसे बाजार के व्यापक लाभों की भी परवाह न करते हुये हमें आलसी तक कह दिया। इतने बड़े लाभों के उपरांत भी जिस प्रकार उसने उसकी घुसपैठ की आवृतियाँ व उसके पैमाने में वृद्धि की है, उससे यह लगता है कि वह हमें सैन्य घुसपैठों से डरा कर अधिक से अधिक सुविधायें हथियाने की रणनीति अपना रहा है। इसलिये भारत की जनता की चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर उसे करारा उत्तर देना चाहिये। हाल ही कुछ घुसपैठ की बड़ी घटनायें यही दर्शाती है। इनमें से कुछ का उल्लेख यहां किया जा रहा है :–

1 **नवम्बर 3 को अरूणाचल में भारतीय सीमा निर्माण में बाधा डालना** : चीनी सैनिकों ने 3 नवंबर को एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के करीब भारतीय इलाके में चल रहे नहर के कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया। आईटीबीपी के 70 और चीन के 55 सैनिक कई घंटे तक आमने–सामने रहे। इस बीच, इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से 29 किलोमीटर नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट सी–17 ग्लोबमास्टर उतार दिया। ग्लोबमास्टर को 6200 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ 4200 फीट लंबे इलाके में उतरना पड़ा। वहाँ चीनी सैनिकों ने कहा कि भारत को लद्दाख में LAC के पास कंस्ट्रक्शन से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। इस घटना में दोनों देशों के सैनिकों ने फ्लैग लगाकर पोजिशन ले ली थी। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी प्रकार 19 जुलाई को उत्तराखंड के चमोली में भी चीनी सैनिक नहर का काम रुकवा चुके हैं। तब भी भारतीय जवानों ने उन्हें वापस भेज दिया था। वर्ष 2014 में भी लद्दाख के निलुंग नाले का काम चीनी सैनिकों ने रुकवाकर मजदूरों के टेंटों को नुकसान पहुंचाया था।

2. **अरूणाचल में सितम्बर 9, 2016 घुसपैठ** : चीन पहले भारतीय सीमा में स्थानीय लोगों को आतंकित कर पलायन को विवश करता है। उसके बाद ऐसे निर्जन क्षेत्रों में घुसपैठ कर वहाँ अपने सुरक्षा बलों के अस्थायी कैम्प बना लेता है। ऐसी ही उसने अभी अरूणाचल प्रदेश के अन्जा जिले की प्लम चौकी तक एक निर्जन क्षेत्र में सीमा पार 45 किमी भारतीय सीमा में घुसकर अस्थायी कैम्प व आशियाने भी बना लिये। सीमा में इतनी गहराई तक आने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र खाली करने को कहने पर इस क्षेत्र को अपना (चीनियों का) बताया। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चीनी सैनिकों को अत्यंत कड़ा रूख अपनाने पर चीनी सैनिकों को 4 दिन बाद 13 जून को इस क्षेत्र को खाली करना पड़ा।

3 **जून 10, 2016 को 250 सैनिकों की घुसपैठ** : अरूणाचल प्रदेश के ही कामेंग जिले के यागत्से क्षेत्र में जून 10, 2016 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 250 जवानों ने घुसपैठ कर ली। वहाँ सीमा क्षेत्र में गश्त का काम चीनी बोर्डर गार्ड्स का है, चीनी सैनिकों का वहाँ आना सुनियोजित घुसपैठ ही कही जा सकती है। भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों द्वारा कड़ा रूख अपनाने के बाद ही वे लौटे हैं। इसी अवधि में चीन 48 सदस्यीय आणविक आपूर्ति समूह में भारत के प्रवेश के विरोध में भी लगा हुआ था।

4 **मार्च 8, 2016 को फिंगर VIII – सिरजेप – I से 5.5 किमी घुसपैठ** : इसी प्रकार के लेह लद्दाख क्षेत्र की ओर भार ठाकुग चौकी से 5.5 किमी अन्दर तक चार वाहनों व भारी शस्त्रास्त्रों साथ चीनी प्लाटून ने घुसपैठ कर के भारतीय बलों पर भारी दबाव उत्पन्न किया। इनमें एक कर्नल व दो मेजर टेंक के अधिकारी दो हल्के वाहन एक मध्यम व एक भारी वाहन था। यह क्षेत्र पेगांग झील के पास पड़ता है, जहाँ वे आये दिन तनाव पैदा करते रहते हैं।

5 **जुलाई 2016 में उत्तराखण्ड में घुसपैठ** : चीनी सैनिकों ने उत्तराखण्ड के चमोली जिले के बारहोती क्षेत्र में 80 वर्ग किमी के चारागाह क्षेत्र में

घुसपैठ कर वहाँ भी तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया। चीन के साथ तनाव न हो, इसलिये वहाँ भारतीय सुरक्षा बल बिना शस्त्र व बिना गणवेश के ही गश्त करत हैं। वैसे भारत इतना संकुचित व सिमटा रहना भी उचित नहीं है। इस क्षेत्र में चीन ने 2013 व 2014 में भी कई बार घुसपैठ की है और हमारी वायु सीमा का भी अतिक्रमण किया है।

इस प्रकार से चीन वर्ष में कुल 300 – 400 बार तक घुसपैठ कर लेता है। अनेक क्षेत्रों में वह इंच दर इंच करके कई क्षेत्रों में स्थायी रूप से भी आगे बढ़ रहा है। ऐसी घुसपैठों व दौलत बैग ओल्डी में 21 दिन तक रहकर भारत की ब्लेकमेलिंग की समीक्षा लेखक ने अपनी तीन अन्य पुस्तकों में किया है।

भारत के सीमा क्षेत्र में विकास की आवश्यकता : चीन ने पूरी 4057 किमी लम्बी भारत तिब्बत सीमा पर अत्यंत व्यवस्थित सड़कें रेलमार्ग, विद्युतीकरण व संचार साधनों का विकास कर लिया है। वह जब चाहे बड़े पैमाने पर सैन्य बल जमा कर सकता है। लेकिन अब वह भारतीय सीमा में किसी भी प्रकार की गतिविधी या हलचल होने पर वहां अडंगा लगा देता है। इसलिये वहाँ के ग्रामीणों को भारी असुविधा होती है। सर्दी में रास्तों से बर्फ हटाने तक की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण परेशानी में पलायन करने तक को विवश हो जाते हैं। चीन चाहता है इन सबसे चीन वहाँ के निवासियों को बताना चाहता है कि यदि वे अपने क्षेत्र में चीन का स्वागत करे तो ही उनके वहाँ सारी नागरिक सुविधायें विकसित होगी।

IV आणविक आपूर्ति समूह में विरोध

भारत ने 48 देशों के आणविक आपूर्ति समूह (न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) की सदस्यता चाही थी। उस समूह के अधिकांश राष्ट्रों ने भारत की सदस्यता के पक्ष में प्रबल समर्थन दिया। लेकिन चीन ने भारत का प्रबल विरोध कर भारत की सदस्यता के प्रस्ताव को इसी वर्ष 2016 के जून में अवरूद्ध का दिया। उसके दोनों ही विरोध के बिन्दु अत्यंत हास्यास्पद थे। उसके द्वारा भारत व पाकिस्तान को समान धरातल पर रखना भी अव्यावहारिक था। केवल चीन के विरोध के कारण ही भारत इस समूह की सदस्यता से वंचित रहा है। यह चीन का भारत विरोध व भारत के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार का एक बड़ा उदाहरण है।

V संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का विरोध

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का इच्छुक है। विश्व के अधिकांश देश भारत के इस दावे का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन चीन ही इसका विरोध कर रहा है। स्मरण रहे जब चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता नहीं मिल पा रही थी, तब 1950 में साम्यवादी देशों को छोड़कर अन्य देशों में भारत ही एक मात्र ऐसा देश था, जिसने चीन की सदस्यता के लिये सर्वाधिक सशक्त आग्रह किया था।

VI पाक अधिकृत कश्मीर में सैन्य उपस्थिति व निर्माण

भारत के सतत विरोध के बाद भी चीन की पीपुल्स लिबटेशन आर्मी के सैन्य प्लाटून व वरिष्ठ अधिकारी वहां बड़ी संख्या में रह रहे हैं। चीन वहाँ स्थायी निर्माण कर रहा है और वहां से राजमार्ग भी निकाल रहा है। आज पाकिस्तान व चीन के पास कुल मिलाकर 1,06,000 वर्ग किमी भूमि अवैध नियंत्रण में है। इसमें 68,000 वर्ग किमी कश्मीर की भूमि पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में व 38,000 किमी भूमि चीन के पास है। चीन ''चीन–पाक आर्थिक गलियारे'' (China Pak Economic Corridor) का 46 अरब डालर अर्थात 3 लाख करोड़ की लागत से विकसित कर रहा है, वह पाक अधिकृत कश्मीर के भारतीय भू–भाग से निकल रहा है। ऐसे में भारत की आपत्ति को उसने ठुकरा दिया। वहाँ यह सारे निर्माण अवैध है क्यों कि उस क्षेत्र की स्थिति को 1947 में पाकिस्तानी आक्रमण से पुरानी स्थिति में लौटाने का संयुक्त राष्ट्र संघ का भी प्रस्ताव है।

अध्याय 2

आर्थिक हितों पर गम्भीर आघात

चीन से बढ़ रहे आयातों से आज देश के अनगिनत उद्योग चौपट हो रहे हैं और चीन को दी निवेश सुविधाओं से अब देश में चीन की आर्थिक उपस्थिति और तेजी से बढ़ रही है। चीन के साथ भारत का विदेश व्यापार घाटा बढ़कर 52.7 अरब डालर हो गया है। यह हमारे कुल विदेश व्यापार घाटे का 45 प्रतिशत है।

विदेश व्यापार के क्षेत्र में भी भारत आज चीन को एक तरफा सुविधाएँ देता चला जा रहा है। 2001–02 तक भारत–चीन व्यापार मात्र 2.09 अरब डालर तक सीमित था। लेकिन 2011–12 में भारत–चीन व्यापार 75.6 अरब डॉलर हो गया और अब 2015 तक भारत–चीन वार्षिक व्यापार 100 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इसमें 2012–13 में चीन को होने वाले भारत के निर्यात एक चौथाई से भी कम है, और चीन से भारत को होने वाले निर्यात 3 गुने हैं। यानि की 75.6 अरब डॉलर के भारत–चीन व्यापार में 2011–12 में हमने जो चीन से आयात किया वह माल 57.5 अरब डॉलर का था, हमने चीन में केवल 18.1 अरब डॉलर का माल बेचा। वर्ष 2012–13 में तो भारत द्वारा चीन को होने वाले निर्यात 18.1 से भी घट कर मात्र 13.5 अरब डालर के ही रह गये। चीन से भारत के आयात, निर्यातों की तुलना में 4 गुने से अधिक 54.3 अरब डालर के थे। इस प्रकार 2012–13 में 67.8 अरब डालर के चीन–भारत व्यापार में हमारा विदेश व्यापार घाटा 41 अरब डालर तुल्य था।

वर्ष 2015–16 में भारत के चीन को निर्यात घट कर 9 अरब डालर के रह गये, उनमें भी अधिकांश कच्चा माल है। चीन को 2012–13 में निर्यात 18.1 अरब डालर के थे। वहीं चीन से हमारे आयात 61.7 अरब डालर हो गये जो हमारे निर्यातों के लगभग 7 गुने है और हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा 52.7 अरब डालर पर पहुँच गया जो हमारे समग्र व्यापार घाटे के 46 प्रतिशत है।

चीन के साथ हमारा यह विदेश व्यापार घाटा विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में सर्वोच्च है। आज जो देश हमारे लिये सबसे बड़ा शत्रु है, उसे हम सर्वाधिक व्यापारिक सुविधाएँ दें यह कितना उचित है? हम चीन को निर्यात में भी अधिकतर कच्चा माल ही बेचते है, जो हमारे लिये भी बहुत कीमती व दुर्लभ है, जैसे 60 प्रतिशत उसमें खनिज लोहा है जो, 50–60 साल में हमारा भी चुक जायेगा। इसी तरह से जैसे कपास, प्राकृतिक रबर आदि जो हमारे उद्योगों के लिये भी उपलब्ध होने आवश्यक हैं। आज भारत दुनिया के 3–4 बड़े रबर उत्पादक देशों में से है और हम अपना रबर अनुदान देकर निर्यात करते हैं। परिणामतः चीन हम से अनुदान पर सस्ता प्राकृतिक रबर खरीदता है। ट्रक और बस का टायर बनाने में 80 से 85 प्रतिशत कच्चा माल रबर के रूप में लगता है। उसे भारत से सस्ता कच्चा रबर मिलने के कारण वह अपने टायर भारतीय टायर निर्माताओं की तुलना में 2000 से 3000 रूपये कम में हमारे यहाँ बेचता है। इसलिए भारतीय बस और ट्रक ऑपरेटर चीनी टायर प्राथमिकता से खरीदते हैं। पूर्व में जो लोग रबर चढ़े हुए टायर लगाते थे वे भी बन्द कर दिए। इससे देशभर में रबर चढ़ाने का काम भी चौपट हुआ है। अब तो एम.आर.एफ. जैसी बडी–बडी भारतीय कम्पनियाँ भी यह कहने लगी कि चीनी टायर सस्ता होने से हम भी अपना कारखाना चीन में लगा रहे हैं। चीन 2007 से हमारे देश में टायर, उसकी लागत से भी कम मूल्य पर बेच कर देश के टायर उद्योग को रुग्ण कर रहा था। लेकिन भारत सरकार ने चीन के टायरों पर एण्टी डम्पिंग ड्यूटी लगाने में छः वर्ष लगा दिये, जिससे देश के टायर उद्योग को भारी क्षति हुयी। यही स्थिति कपास की है। वर्ष 2011 में देश का अधिकांश कपास चीन ने अत्यन्त ऊँची कीमत पर इसलिये खरीद लिया कि इससे हमारे देश के सूती वस्त्र उद्योग को कपास नहीं मिले। इससे हमारा सूती वस्त्र निर्यात गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ और भारत का निर्यात बाजार छीनने के लिये चीन ने अपने परिधान भारत में निर्यात बाजारों में अत्यन्त सस्ते बेचने प्रारम्भ कर दिये। देश का टायरों का 40 प्रतिशत रीप्लेसमेण्ट बाजार चीन ने हथिया लिया है चीनी टायर बिना वारण्टी के घटिया होने से उनकी एक्सीडेण्ट दर भी उच्च है।

पांच वर्ष पूर्व फैडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स इण्डस्ट्री (फिक्की) ने लघु और मध्यम उद्योगों का एक सर्वे किया था। इस सर्वेक्षण में 74 प्रतिशत उद्यमियों ने यह कहा कि उनको चीन के उत्पादों से कड़ी स्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है और 62 प्रतिशत ने यह सम्भावना व्यक्त की कि चीन के सस्ते उत्पादों के कारण सम्भव है आने वाले 3–4 वर्षों में हमें किसी भी दिन अपना कारखाना बन्द करना पड़े, क्योंकि चीन के अत्यन्त सस्ते उत्पाद देश में आ रहे है। आज वह सही हो रहा है। अब चाहे वे प्रिन्टिंग या अभियान्त्रिकी के व इलेक्ट्रानिक उत्पाद हों या कोई रसायन व औषधियाँ हो, लगभग सभी प्रकार के चीनी उत्पाद इतने सस्ते आ रहे हैं कि एक–एक कर देश के कारखाने बन्द हो रहे हैं। लेकिन, दुर्भाग्यवंश हम संभवतः चीन को यह सोच कर अधिकाधिक व्यापारिक सुविधाएँ दे रहे हैं कि अगर हम उदार व्यापारिक सुविधाएँ देते चलेंगे तो वह सीमा पर थोड़ा कम दबाव बनायेगा, तो यह एक दिवा स्वप्न है। वहीं देश के उद्यमियों ने जो सम्भावना व्यक्त की वह आज सही सिद्ध हो रही है। देश के अनेक उद्योग पूरी तरह समाप्त हो गये। बिजली, इलेक्ट्रानिक्स व कई रसायनों के उद्योग देश में बन्द हो गए है। देश का रसायन उद्योग, दवा उद्योग भी चीनी स्पर्द्धा कठिनाई अनुभव कर रहा है। देश में इलेक्ट्रानिक उद्योगों के बंद होते चले जाने से छात्रों ने इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में तो प्रवेश लेना ही कम कर दिया है। चीनी लीनोवो कम्प्यूटर ही आज देश में सर्वाधिक बिकता है। इससे देश की जो मात्र 2 कम्प्यूटर हार्डवेअर बनाने वाली इकाईयाँ थीं, वे भी बन्द हो गयी। जेनिथ का कम्प्यूटर व विप्रो का जो कम्प्यूटर हार्डवेअर इकाई थी वह बन्द हो गयी। कम्प्यूटर में भी चीन पर देश का अवलम्बन इतना बढ़ गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को अनुदान पर आई.आई.टी., मुम्बई को जिस आकाश टेबलेट पी.सी. के विकास का दायित्व दिया। उसके विकास में आई.आई.टी. को सफलता नहीं मिलने पर उसने (आई.आई.टी., मुम्बई ने) यह काम, दो भारतीयों की कनाडा स्थित कम्पनी

'डेटाविण्ड' को दे दिया। इस पर 'डेटाविण्ड' ने चीनी बाजार में 42 डालर में उपलब्ध एक टेबलेट पी.सी. को लाकर आई.आई.टी. को सौप दिया। तब आई.आई. टी. मुम्बई ने इसे भारतीय आविष्कार कह इसका महामहिम राष्ट्रपति से भारत मे विकसित टेबलेट पी.सी. कहकर उद्घाटन भी करा लिया और उसे एक भारतीय आविष्कार की तरह संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को भी प्रस्तुत कर दिया। वस्तुतः भारत को आज प्रौद्योगिकी विकास में स्वयं पहल करनी चाहिये। चीन ने अपने यहाँ (50 अरब डालर का अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक उत्पाद विकास केन्द्र स्थापित करने का भी निर्णय किया है)

भारत में चीन का निवेश भी तेजी से बढ़ा है। विगत 13 वर्षों में 142 चीनी कम्पनियों ने भारत में 27 अरब डालर का निवेश किया है। इनमें Huawe, ZTE, Alibaba, Xiomi आदि प्रमुख है। हाल ही में चीन ने भारत देश की अत्यंत प्रतिष्ठित औषधि निर्माता कम्पनी ग्लाण्ड फार्मा को भी में खरीदने का सौदा किया है। चीन विश्व भर में जिस गति से कम्पनियों का अधिग्रहण कर रहा है, उससे वह और भी द्रुत गति से भारत सहित विश्व बाजारों में छा जायेगा। हाल ही में उसने 'Haier' अमेरिकी कम्पनी जी.ई. एप्लायन्सेज (G.E Appliances) को 5.4 अरब डालर व स्विस कृषि रसायन व बीज कम्पनी सिन्जेण्टा (Syngenta) को 43 अरब डालर में खरीदने का सौदा किया है। भारत में भी सिंजेण्टा का बड़ा कारोबार है। वर्ष 2016 की प्रथम तिमाही में ही चीन ने विश्व में 86 अरब डालर के अधिग्रहण का सौदा किया है। शीघ्र ही चीन का आर्थिक पंजा और इतना सशक्त हो जायेगा कि उससे भारत की कठिनाईयां और बढ़ जायेगी।

चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा, उद्यम बन्दी का संकट : देश का सर्वाधिक व्यापार घाटा आज चीन के साथ है, जो निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। वर्ष 2015 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 51.9 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। यह देश के कुल व्यापार घाटे का 46 प्रतिशत है। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि भारत से चीन को होने वाले निर्यात मात्र 9.6 अरब डॉलर के हैं जबकि भारत में चीन के निर्यात इसके पौने सात गुने, अर्थात् 61.5 अरब डॉलर के हैं। इसलिए चीन के साथ भारत के कुल 71.22 अरब डॉलर के व्यापार में 51.8 अरब डॉलर का घाटा है। भारत से चीन को होने वाले निर्यातों में भी कच्चे माल की ही अधिकता है जिसमें सर्वाधिक मात्रा कच्चे खनिज लोहे की है। दूसरी ओर भारत को होने वाले चीन के सारे निर्यात विनिर्मित वस्तुओं के हैं। ऐसा द्विपक्षीय व्यापार असन्तुलन विश्व में कहीं भी दो व्यापारिक साझोदारों में नहीं है। वह भी तब, जबकि चीन हमारे साथ निरन्तर शत्रुवत व्यवहार करता रहा है। चीन से बढ़ रहे आयातों के कारण ही देश में आज बड़े पैमाने पर उद्योग बन्द होते जा रहे हैं। देश में बैंकिंग क्षैत्र की अनिष्पादनीय आस्तियों (Non Performing Assets) में भारी वृद्धि का भी सबसे बड़ा कारण चीन से निरंकुश गति से बढ़ रहे आयातों से फैल रही औद्योगिक रूग्णता है। आज लिखने के पेन व बल्ब से लेकर पर्सनल कम्प्यूटर्स (P.C.), मोबाईल फोन, बिजली के साज सामान और सौर ऊर्जा संयंत्रों तक सभी उद्योग वर्गों में बढ़ रहे चीनी आयातों की वृद्धि से ही देश में उद्यम बन्दी, डी इण्डस्ट्रेलाईजेशन और (Non Performins Assets) अनिष्पादनीय आस्तियों में वृद्धि हो रही है। देश की वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भी चीन से बढ़ रहे आयातों के कारण देश के सूक्ष्म लघु व मध्यम आकार के उद्यम (MSME) सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। उनके द्वारा संसद में दिए उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित 12 प्रमुख उत्पाद समूहों में वर्ष 2011–12 से 2014–15 के बीच, चीन से होने वाले आयातों की वृद्धि शेष विश्व के सभी देशों से हुई संयुक्त आयात वृद्धि की तुलना में भी सर्वाधिक है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वर्तमान में चल रहे 322 राशिपतन–रोधी मामलों (Anti Dumping Cases) में सर्वाधिक 177 मामले चीन से संबंधित है।

सर्वाधिक आश्चर्यजनक तो यह है कि एक ओर तो देश के अधिकांश सौर ऊर्जा संयंत्रों के विनिर्माणी उद्यमों (Solar Power Equipment Manufacturing Units) की प्रगति अवरूद्ध हो रही है और वे रूग्ण होते जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर पूरे देश में चीनी सौर ऊर्जा पेनल्स व संयंत्रों का आयात तेजी से बढ़ रहा है। आज देश में 80 प्रतिशत सोलर पेनल चीन से ही आ रहे हैं। कई स्थानों पर सोलर पार्क लगाने के ठेके भी चीनी कम्पनियों को ही जा रहे हैं। इसके कारण आगामी वर्षों में चीनी कम्पनियाँ भारी मात्रा में देश से विदेशी मुद्रा बाहर ले जाएंगी। अमेरिका तक को उसके घरेलू उद्यमों को बचाने के लिए चीनी सोलर पेनल्स पर 238 प्रतिशत तक की एन्टी डम्पिंग ड्यूटी लगानी पड़ी है। भारत में भी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सस्ती डम्पिंग की शिकायत मिलने के संबंध में अनुसंधान करने पर डम्पिंग अर्थात् राशिपतन के प्रमाण पाये गये हैं व ऐसा पाये जाने पर राशिपतन रोधी (एण्टी–डम्पिंग) शुल्क लगाने की अनुशंसा भी की गई थी। लेकिन, वित्त मंत्रालय ने जानबूझ कर निर्धारित अवधि में एन्टी डम्पिंग ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णय ले लिया। इससे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत भारतीय उद्यमों को भारी धक्का लगा है। इसलिए अब चीन मलेशिया, ताईवान, अमेरिका व यूरोप की सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादक कम्पनियाँ भारी मात्रा में सस्ती डम्पिंग कर भारतीय उत्पादकों को नुकसान पहुँचा रहीं हैं।

यही स्थिति देश में बस व ट्रक टायर उत्पादकों की भी हो रही है। टायर उद्योगों के संघ के अनुसार विगत 2 वर्षों में देश में बस व ट्रक के रेडियल टायरों के आयात में 2.5 गुनी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2014 में देश में बस व ट्रक रेडियल्स का मासिक आयात 40 हजार टायर था जो वित्तीय वर्ष 2014–15 में बढ़कर 65 हजार टायर प्रतिमाह हो गया और 2015–16 में 1 लाख टायर प्रतिमाह हो गया। देश में टायरों का अधिकांश आयात चीन से ही हो रहा है। टायरों के कुल आयात में चीनी टायरों का अनुपात एक ही वर्ष में 2 गुना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में देश में होने वाले कुल आयातों में चीन का अंश 40 प्रतिशत था। 2015–16 में बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया है। आज देश में बस व ट्रक टायरों की कुल मांग (Replacement Demand) की 30–40 प्रतिशत की पूर्ति चीनी टायरों से हो रही है। इसके कारण देश में टायर उद्योग रूग्ण व समस्याग्रस्त हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में ही बस व ट्रक टायरों का आयात 7.8 लाख वार्षिक आयात से बढ़कर 12.8 लाख टायर प्रतिवर्ष हो गया है जो 2013–14 में मात्र 4.9 लाख टायरों का ही था। इस प्रकार ट्रक व बस टायरों का आयात एक वर्ष में ही 64 प्रतिशत बढ़ गया है। अमेरिका तक ने चीनी आयातों से घरेलू टायर उद्योग बचाने के लिए अत्यन्त ऊँचा राशि पतन रोधी शुल्क और अनुदान संतुल्यकारी शुल्क लगाया है। इसके कारण देश में रबर उत्पादक भी प्रभावित हो रहे है। मोबाईल फोन के बाजार पर भी चीनी कम्पनियों का फैलता साम्राज्य : देश के अन्य सभी उद्योगों के साथ–साथ अब स्मार्ट फोन के बाजार पर भी

चीनी कम्पनियों का ही साम्राज्य फैल रहा है। कण्ट्री पॉइण्ट टेक्नालाजी रिसर्च नामक अनुसंधान के अनुसार वर्ष 2013 की प्रथम तिमाही में देश में चीनी स्मार्ट फोन के मात्र 12 ब्राण्ड उपलब्ध चलन में थे जिनकी संख्या 2015 की प्रथम तिमाही तक बढ़कर 57 हो गयी। इस प्रकार 2 वर्ष में ही भारतीय बाजारों में चीनी ब्राण्डों की संख्या 12 से बढ़कर 57 अर्थात् पौने पाँच गुनी हो गयी है। भारत के स्मार्ट फोन के बाजार में चीनी ब्राण्डों का हिस्सा 2014 में मात्र 15 प्रतिशत था जो बढ़कर 2015 में 22 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2016 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 24.4 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर स्मार्ट फोन के भारतीय ब्राण्डों का बाजार अंश 5 प्रतिशत घट गया है। चीनी ब्राण्डों के दबाव में अन्य वैश्विक ब्राण्डों का बाजार अंश भी 1 प्रतिशत घटा है। स्मार्ट फोन के चीनी ब्राण्डों यथा हुवेई, लिनोवो, मोटो, जिओमी, जिओनी, वन प्लस, वेगो, ओप्पो, मिजु, लिको, पूल पेड आदि की बिक्री भारतीय बाजारों में तेजी से बढ़ रही है। इसी प्रकार देश का बिजली का बल्ब उद्योग, काँच उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, फर्नीचर उद्योग आदि सभी उद्योग चीनी आयातों से प्रभावित हुए हैं।

चीन से इस बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए उस पर नियंत्रण के लिए चीनी कम्पनियों को देश में निवेश व उत्पादन की सुविधाएँ देने का प्रस्ताव और भी घातक है। चीनी आयातों पर अंकुश लगाने के कई विधि सम्मत मार्ग हैं लेकिन, चीन के द्वारा देश में एक बार निवेश कर लेने के उपरान्त उन क्षेत्रों से उसे वापस लौटाना कभी भी संभव नहीं होगा। चीनी उद्यमों द्वारा अपने इस निवेश के लाभों के पुनिर्निवेश से और लाभों को देश से बाहर ले जाने से कई नयी समस्याएँ खड़ी होंगी। इसलिये देश के विदेश व्यापार में घाटे पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चीनी आयातों पर नियन्त्रण अति आवश्यक है। इसके विपरीत चीन को इन उत्पादों के लिए देश में उत्पादन की सुविधा देना तो और भी खतरनाक है। इसलिये विदेश व्यापार में घाटे पर अंकुश लगाने के लिए चीन से हो रही निरंकुश आयात वृद्धि पर तत्काल प्रभावी रोक अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु आयातित वस्तुओं के संबंध में गुणवत्ता के राष्ट्रीय प्रमाप भी स्थापित किये जाने चाहिए। इनके अतिरिक्त समयोचित राशिपतन रोधी (एन्टी डम्पिंग) शुल्क और अनुदान समतुल्यकारी शुल्क (काउन्टर वेलिंग ड्यूटी) भी समुचित मात्रा में लगायी जानी चाहिये। देश के व्यापार घाटे में नियन्त्रण हेतु सर्वप्रथम चीन के साथ बढ़ रहे व्यापार घाटे पर तत्काल नियन्त्रण आवश्यक है।

अध्याय 3

भारत की घेराबंदी व हमारी ऐतिहासिक गलतियां

चीन व पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां

चीन में 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना और 1947 में पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के समय से ही चीन व पाकिस्तान भारत के विरूद्ध निरंतर शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों में लिप्त रहे हैं। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके लगभग पूरे स्विट्जरलैंड के क्षेत्रफल (41,000 वर्ग किमी.) जितने 38,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल के अक्साई–चिन पर अधिकार कर लिया था, जो आज तक उसी अधिकार में है। इसके साथ ही आज वह प्रतिवर्ष 300 से 400 बार हमारी सीमा में घुसपैठ करता है और इन्हीं घुसपैठों के माध्यम से इंच दर इंच आगे बढ़ते हुए हमारे कई अत्यंत उर्वरा चारागाह क्षेत्रों पर अधिकार व अचाई वाले रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर अधिकार करता जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ भारत के 1947, 1965, 1971 और 1999 में खुले युद्ध हो चुके हैं। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद से आज कश्मीर सहित पूरा देश युद्ध से भी अधिक गम्भीर रक्तपात का सामना कर रहा है।

भारत की ऐतिहासिक गलतियां

भारत ने 1950 में सरदार पटेल द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखकर चीन के खतरों के प्रति, तब ही सावधान कर दिया था। उसके बाद भी भारत द्वारा तिब्बत को चीन का संरक्षित राज्य बनाना बहुत बड़ी भूल थी। यदि 1949 की भुटान के साथ की गई संधि के अनुसार ही चीन के साथ भी भारत ने वैसी ही संधि कर ली होती तो भारत व चीन के बीच तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में होता। ऐसी ही गलती जवाहरलाल नेहरू ने पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के नियंत्रण में छोड़कर युद्ध विराम की घोषणा कर दी और जम्बू कश्मीर की 68,000 वर्ग किमी भूमि पाकिस्तान के नियंत्रण में छोड़ दी।

कश्मीर पर 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के बाद भारत की आगे बढ़ती सेनाओं को रोक कर युद्ध विराम घोषित कर देने से ही आज पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में देश की 68 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि पाकिस्तान के अधिकार में है। इसमें से 5139 वर्ग किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्रफल पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। चीन को दिये इसी क्षेत्र में से निकल रहे कारकोरम राजमार्ग के माध्यम से ही चीन व पाक के बीच सीधे धरातलीय संपर्क एवं सड़क मार्ग का निर्माण संभव हुआ है। यदि जवाहर लाल नेहरू ने अदूरदर्शिता पूर्वक राष्ट्रीय हित की अनदेखी करके जम्मू कश्मीर का यह पाक अधिकृत क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में नहीं छोड़ा होता तो, पाकिस्तान व चीन के बीच यह धरातलीय सम्बन्ध व सड़क संपर्क कदापि संभव नहीं होता। इसके विपरीत, भारत व अफगानिस्तान के बीच सीधा धरातलीय व सड़क मार्ग से सीधा सम्पर्क हो सकता था। तब अफगानिस्तान के रास्ते भारत का मध्य एशियाई गणराज्यों यथा तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजस्तान, उजबेकिस्तान, कजाखिस्तान, आर्मेनिया व रूस पर्यन्त व पश्चिम में ईरान व ईराक तक तक के साथ सीधे सड़क मार्ग से सम्पर्क भी संभव था। वहां से आगे भारत अरब, अफ्रीका व यूरोप से सीधे सड़क मार्ग से सम्पर्क जोड़ सकता था।

स्मरण रहे कि 1947 में जब भारतीय सेना द्रुत गति से पाकिस्तानी सेना को कश्मीर से खदेड़ रही थी और पीछे हटते पाक सैनिकों के प्राण भी संकट में थे, तब अंग्रेज गर्वनर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बहकावे में आकर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रीमण्डलीय सहयोगियों की राय की भी अनदेखी कर, देश की वह अत्यन्त महत्व की 38,000 वर्ग किमी. भूमि पाकिस्तान के नियंत्रण में ही छोड़कर युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। माउंटबेटन जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दिलाना चाहते थे और जवाहर लाल नेहरू स्वाधीनता के बाद भी अकारण ही माउंटबेटन की आज्ञा में चलते रहे। इसलिये जवाहर लाल नेहरू की अदूरदर्शिता और उनके माउंटबेटन के जम्मू कश्मीर भारत विरोधी षडयंत्रों का शिकार बन जाने के कारण गिलगिट, बालटिस्तान सहित जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा भाग पाकिस्तान के नियन्त्रण में छोड़ देने के कारण ही चीन के लिए वहां से सीधे ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचना संभव हुआ है, जहां चीन ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाकर अरब सागर में भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां खड़ी कर रहा है। अन्यथा चीन कभी भी अरब सागर में भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां खड़ी नहीं कर सकता था। माउण्टबेटन के दबाव में ही जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सातवें अध्याय में पाकिस्तान को एक आरोपी न बना कर छठे अध्याय में उठा कर पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर विवाद में भारत के विरूद्ध एक पक्षकार का सम्मानजनक स्थान किया। छठे अध्याय में दो राष्ट्रों के बीच ऐसे विवाद के शान्तिपूर्ण हल का आग्रह किया जाता है, जिसका वे समाधान उन्हें ही स्पष्ट न हो। चूंकि पाकिस्तान आक्रमणकर्त्ता देश था और उसने शान्ति भंग की थी। शान्ति के लिये संकट उपजाने वाले, शान्ति भंग करने वाले और आक्रमण के दोषी है ऐसे आरोपी देशों के मामले चार्टर के सातवें अध्याय में उठाये जाते हैं। नेहरू ने यह मामला सातवें के स्थान छठे अध्याय में उठाकर अकारण पाकिस्तान को एक पक्षकार का स्थान दे भारत का पक्ष कमजोर किया। यहाँ पर इस विषय का विस्तार तो हो रहा है। लेकिन, यह भी स्पष्ट कर देना अप्रासंगिक नहीं है कि जम्मू–कश्मीर के विलय का प्रस्ताव लेकर अन्य 541 रियासतों की तरह सरदार पटेल व वी.पी. मेनन को नहीं भेज कर वहाँ माउण्टबेटन की जिद पर भारत की और से प्रस्ताव लेकर माउण्टबेटन को भेजा जो जम्मू–कश्मीर का विलय पाकिस्तान में कराने का वचन जिन्ना को दे चुके थे और उन्होंने कश्मीर के महाराज हरिसिंह को जम्मू–कश्मीर का विलय प्रारम्भ में पाकिस्तान में करने का सुझाव दिया था व दूसरे विकल्प की दशा में उनके जीवन को खतरे का भय दिखाया। उस बात पर महाराजा हरिसिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया था। अन्यथा सरदार पटेल को विलय प्रस्ताव लेकर कश्मीर जाने दिया होता तो

कश्मीर का विलय पहले ही भारत में हो जाता। उस समय के भारतीय नेतृत्व की गललियों का परिणाम हम आज सह रहे हैं। वैसी ही गलती हम आज देश में चीनी वस्तुओं की भरमार से देश में उद्यम बन्दी, भारी विदेशाी व्यापार घाटे, उसके कारण रूपये के अवमूल्यन और देश से अनेक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विलोपन की कीमत पर चीन की अर्थव्यवस्था का आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। देश में अधिकारिक रूप से 4 लाख करोड़ रूपयों का चीनी माल व अनाधिकृत से भी लगभग इतना ही माल देश में चीन से आकर हमारे उद्योगों व हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है।

आज चीन व पास्किातान परस्पर तालमेल के साथ षडयंत्र रचकर भारत के लिए अनेक प्रकार से सुरक्षा समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान एक प्रकार से चीन का एवजी युद्ध अथार्त प्रॉक्सी वार (proxy war) लड़ रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन के द्वारा जिस प्रकार के षड़यंत्रों से भारत की सामरिक, आर्थिक व राजनैतिक घेराबंदी की जा रही है, उसे देखते हुए भारत के नागरिकों को चीनी उत्पाद का पूर्ण बहिष्कार कर, चीन की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने में संनद्ध हो जाना चाहिए। चीन जिस प्रकार से विश्व शांति में बाधक, मानवाधिकारों के हनन और पर्यावरण संकट का पर्याय बनता जा रहा है, उसे देखते हुए भारत के जागरूक नागरिकों को संपूर्ण विश्व में भी चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवाहन करना चाहिए। चीन जिस प्रकार से मानवता व पर्यावरण के विरूद्ध इन सभी दुष्चक्रों में लिप्त है उन्हें देखते हुये भारत का आम नागरिक चीनी उत्पादों के विश्व व्यापी बहिष्कार का आवाहन करके विश्व मानवता के लिए संकट का कारण बनने वाले चीन के षडयंत्रों से विश्व समुदाय को बचा सकता है। चीन के द्वारा तिब्बत, नामीबिया, इक्वेटोरियल गिनी, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, श्रीलंका, सूडान, अंगोला आदि में मानवाधिकारों के हनन या ऐसे हनन में सक्रिय संलिप्तता व पर्यावरण विनाश के कार्यों का विवेचन लेखन की चीन पर लिखित 4 पूर्व पुस्तकों में किया जा चुका है।

इसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु का भ्रम था कि हम अगर पड़ौसी चीन को नई–नई सुविधाएँ देंगे और उसे तिब्बत को हड़प लेने में भी सहयोग कर देंगे तो उससे हमारे सम्बन्ध अच्छे होंगे। इसलिए 1950 में जब तिब्बतियों ने भारत के साथ रहने और भारत का प्रोटेक्टोरेट बनने की इच्छा व्यक्त की थी। हमने वह सन्धि चीन के साथ करा दी। 35चूकि 1949 में भूटान ने भारत से सन्धि कर वह भारत का संरक्षित (Protectorate) राष्ट्र बन गया था। बाद में 2004 में भारत सरकार ने उसका भी समय पर नवीनीकरण नहीं किया, और बाद में भी उसे विरल कर दिया। वह एक अलग विषय है। लेकिन, तब 1949 में भूटान के रक्षा व विदेश मामलों का दायित्व भारत ने ले लिया था। तिब्बत भी तब भारत से ऐसी ही मैत्री सन्धि करना चाहता था। तब इसके विपरीत हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने तिब्बती लामाओं को परामर्श दिया कि आप लोग भारत नहीं चीन के प्रोटेक्टोरेट बनिये और उन्होंने 1951 में एक सन्धि करवाई जिसमें जवाहरलाल जी ने आश्वासन दिया कि आपकी (तिब्बत की) आंतरिक स्वायत्तता व संस्कृति और आंतरिक स्वशासन कायम, रहेगा यह मै आश्वस्त करता हूँ। आप चीन के साथ सन्धि कर उसकी सम्प्रभुता स्वीकार कर लीजिये। तब जाकर तिब्बतियों के नेतृत्व ने, नेहरू जी के भरोसे वह 17 सूत्री संन्धि की थी। इसके पूर्व, तिब्बत एक स्वतन्त्र राष्ट्र था। उसके बाद 1955 से चीन ने वहाँ अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ानी शुरू कर दी और वर्श 1959 में तो चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तब पूज्य दलाईलामा को भारत में शरण लेनी पड़ी थी।

इससे पहले 1951 से 1955 तक चाऊ एन लाई, जवाहरलाल जी को बराबर कहते थे कि चीन व भारत के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। हमारी सीमाएँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन, तिब्बत पर पूर्ण अधिकार करते ही 1955 से चीन ने कुछ ऐसे नक्शे जारी करने शुरू किये, जिनमें भारतीय भू–भाग को चीन का बताना आरम्भ किया और 1959 में तिब्बत पर पूर्ण नियन्त्रण होते ही उन्होने कह दिया कि हमारे (भारत व चीन के) बीच गम्भीर सीमा विवाद है और चीन की एक लाख, चार हजार वर्ग किलोमीटर जमीन आपने (भारत ने) दबा रखी है। इस प्रकार जब तक तिब्बत को हड़पने के लिये भारत का सहयोग चीन को चाहिये था, तब तक कहा कि हमारे (चीन–भारत के) बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। जैसे ही उसने तिब्बत को पूरी तरह से अधिगृहित कर लिया एकदम कह दिया कि भारत ने चीन की एक लाख, चार हजार वर्ग किलोमीटर जमीन दबा रखी है। स्मरण रहे उसके पूर्व, जब चीन संयुक्त राश्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, तब कम्युनिस्ट देशों को छोड़ कर भारत ही एक मात्र देश था, जिसने चीन की सदस्यता के लिये सर्वाधिक प्रबल समर्थन दिया था। इन सारे उपकारों को भुलाकर अन्ततः 1962 में तो भारत पर आक्रमण कर के हमारी 38,000 वर्ग किमी. भूमि चीन ने बलात् अधिग्रहित कर ली। इस प्रकार चीन से शान्ति खरीदने की भ्रान्तिवश तिब्बत को चीन को सौंपने की जो बहुत बड़ी भूल तब भारत ने की थी, उसके कारण एक ओर तो चीन सीधे हमारा पड़ौसी बन कर आज सीमा पर अनुचित दबाव बना रहा है। यदि वहाँ स्वतन्त्र तिब्बत होता तो उत्तर से हम पूरी तरह सुरक्षित होते।

तिब्बत कभी भी चीन का अंग नहीं रहा है। यह भिन्न बात है कि मध्य युग में थोड़े समय तिब्बत और चीन दोनों ही कभी मंगोल साम्राज्य में रहे हैं और मंगोलिया से जिस समय चिंगीज हान् जिसको अक्सर इतिहासकार कह देते है, चंगेज खान, और यह भ्रान्ति हो जाती है कि वह एक मुसलमान था, जबकि चिंगीज हान बौद्ध था और उसने बौद्ध होने के कारण भारत के प्रति स्वभाविक सम्मान के कारण, तब आक्रमण नहीं किया था और अरब तक वह गया था। दूसरा पारम्परिक व प्राचीन इतिहास की दृष्टि से देखें तो, तिब्बत यानि कि 'त्रिविष्टप', भारत का अंग ही रहा है। तिब्बत स्थित कैलाश–मान सरोवर भारत के अभिन्न अंग रहे है।

कैलाश–मान सरोवर के वर्णन और यहां तक कि रामायण और महाभारत में, भी चीन और 'त्रिविष्टप' का वर्णन आता है और शालिवाहन द्वारा प्रवृत्त शक संवत के चलन के समय ईस्वी वर्ष 78 में 1925 वर्ष पूर्व भारत की सीमा अर्थात् उस समय भारत के साम्राज्य की सीमा, चीन के 'सिंकियाँग' प्रान्त तक थी और इधर अफगानिस्तान से आगे, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमिनस्तान, ये सब भारतीय साम्राज्य के भाग थे और तब देश की राजधानी पेशावर (अब पाकिस्तान) में थी, वहां उसका 13 मंजिल का उस समय जो राजधानी का भवन था, उसके अवशेषों को, मो. गौरी के साथ आये मुस्लिम इतिहासकार अल–बेरूनी ने देखे थे और उसने ही अपने दसवीं शताब्दी में लिखी तवारीख अल हिन्द ग्रन्थ में यह वर्णन लिखा है कि पहली सदी के पेशावर में

भारत की राजधानी के उन अवशेषों को तब 10वीं सदी में भारत आने के समय उसने देखे हैं। दक्षिण एशिया से रोम को जोड़ने वाले सिल्क रुट पर भारत का नियन्त्रण था। तब भारत का विस्तार तिब्बत व चीनी प्रान्त सिंकियांग तक रहा है। 37लेकिन चीन का कभी भी, जो हिमालय की 'वाटर–फाल लाइन' हिमालय की सर्वोच्च चोटीयों से जहां से पानी इधर गिरता है, वह भारतीय हिस्सा कहलाता है, इस भारतीय क्षेत्र पर, चीन का कभी भी साम्राज्य नहीं रहा तिब्बत के स्वतंत्र राज्य की अवधि में तिब्बत का भी नहीं रहा है।

चीन में जब 1949 में कम्यूनिस्ट शासन बना था, तब भारत उन 6–7 राष्ट्रों में प्रमुख था, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्यता दिलाने में सर्वाधिक वकालत की थी और जो तिब्बत के साथ सन्धि हुई थी चीन की, वह भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ही 1951 मई में करायी थी। जब तिब्बत पर चीन का बराबर दबाव बढ़ा रहा था, तब तिब्बती लोग, भारत पर अधिक विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने भारत से मैत्री सन्धि करनी चाही व जवाहरलाल नेहरू से यह आग्रह किया कि वे तिब्बत को भारत का 'प्रोटेक्टरेट' बनाना चाहते थे। जैसा कि पूर्व में वर्णन किया गया है कि तिब्बती लामा चाहते थे कि भारत ने जैसी मैत्री सन्धि भूटान से की है, जिससे भूटान की रक्षा व विदेश सम्बन्ध, भूटान के भारत को सौप दिये थे, वैसी ही सन्धि भारत–तिब्बत के साथ भी कर लेवे। परन्तु पंडित नेहरू ने, तब उन्हें इसके विपरीत यह कहा कि नहीं, तुम चीन से मैत्री सन्धि कर चीन के प्रोटेक्टरेट बन जाओ। तुम्हारे 'एक्सटरनल' रिलेशन्स और तुम्हारा 'डिफेन्स' इन दो बातों का दायित्व चीन लेगा, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी चीन लेगा और मै आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी आन्तरिक स्वायतता बनी रहेगी। ऐसा पंडित नेहरू ने आश्वस्त किया तब उन्होंने मई, 1951 की संधि पर चीन के साथ हस्ताक्षर किये थे। सम्भवतः जवाहरलाल नेहरू रूस के अत्यधिक प्रभाव में थे कि उन्होंने कम्यूनिस्ट रूस को प्रसन्न करने के लिये तिब्बत कम्यूनिस्ट चीन की झोली में डाल दिया। वस्तुतः 1914 की भारत, चीन व तिब्बत की त्रिपक्षीय सन्धि के अनुसार तिब्बत एक स्वतंत्र राश्ट्र था। यदि वर्ष 1950 का तिब्बती लामाओं का प्रस्ताव मान कर जवाहरलाल नेहरू ने, भूटान की भांति तिब्बत को भी भारत का संरक्षित राष्ट्र (Protectorate) बना लिया होता और उसे यदि चीन को उपहार स्वरूप नहीं सौंप दिया होता। तब तिब्बत भारत–चीन के बीच एक प्रभावी सुरक्षा दीवार सिद्ध होता। ब्रह्मपुत्र सहित, विश्व के 11 देशों को जलापूर्त्ति कर रही वे 10 नदियाँ चीन के नियन्त्रण मे नहीं जाती जो आज चीन के नियन्त्रण मे हैं। उन नदियों के जल को आज चीन हड़पने जा रहा है। हमारे सिरी जेप क्षेत्र में IV तक नियन्त्रण रेखा से 5 किमी. अन्दर तक चीन ने सड़क बना दी है। अरूणाचल प्रदेश के भारतीय भू–भाग पर चीन अपना हेलीपेड बना चुका है और परम्परा से अरूणाचल प्रदेश के चरवाहे जितनी ऊंचाई तक पशु–चराने जाते थे, उन्हें, चीनी सैनिकों ने मनाही कर दी है।

भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, चीन ने जम्मू–कश्मीर के भारतीयों को अलग पत्र पर वीजा देने की खुराफात शुरू की है। जम्मू–कश्मीर के लिये उसने भारत अधिकृत कश्मीर (India Occupied Kashmir) कहना आरम्भ कर दिया है। अरूणाचल प्रदेश को छद्म रूप से अपना सिद्ध करने हेतु उसने चीन जाने वाले अरूणाचल प्रदेश के निवासियों को यह कह कर कि उन्हें वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। चीन बहुत चतुराई से नाप–तोल कर दबाव बनाता है। उसकी 14 देशों के साथ सीमाएं लगती है, जो देश जब कमजोर था, या जब जिस देश पर चीन अपनी दादागिरी जमा सकता था, सौदाबाजी में दबाव डालकर अपनी बात मनवा सकता था, तब–तब उसने, उस देश के साथ अपना सीमा विवाद हल किया। म्यानमार व बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद उसने पहले हल कर लिया। सोवियत संघ के साथ भी उसका विवाद था, तो जब तक सोवियत संघ इकट्ठा था तब तक वह चुप रहा और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसने, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, सोवियत रूस आदि सभी के साथ अपनी शर्तों पर सीमा विवाद हल कर लिये। क्योंकि, अब वह एक ताकतवर देश था। इसलिए अपने पक्ष में सारे समझौते करवा लिए। अब उसका सीमा विवाद भारत से ही बचा है।

हमें स्मरण होगा कि, वाजपेई जी जब विदेश मंत्री थे तब 1989 में चीन गये थे उस समय उसने वियतनाम पर भारी आक्रमण कर दिया था और काफी आगे तक बढ़ गया था। तभी से उनकी वार्ता प्रारम्भ हो गई थी, जो 1999 में जाकर उनका सीमा विवाद पर समझौता हुआ। जो स्वभाविक रूप से चीन के पक्ष में हुआ। जैसा अभी कहा गया कि सिक्किम को भारत का अंग मानने की चीन, अनौपचारिक तथा औपचारिक घोषणा कर चुका है। फिर भी पिछले 3–4 वर्षों से पुनः उसे विवादास्पद क्षेत्र बताया जा रहा है चीन, बयान बदल कर बोल रहा है। तो इस प्रकार से उसका दबाव हम पर बना हुआ है। अब इस दबाव के साथ–साथ उसने भारत की एक प्रकार से घेराबंदी शुरू कर दी है। भारतीय उपमहादीप व हिन्द महासागर क्षेत्र में जितने छोटे–छोटे देश है, उन सबका वह संरक्षक बनता जा रहा है, ताकि भारत से इन देशों की कूटनीतिक दूरी बढ़े तथा जो देश अब तक भारत के निकट रहे हैं, समर्थक रहे हैं, वे चीन के निकट समर्थक बनें, भारत के विरोध में खड़े हो, इस प्रकार की घेराबन्दी कर रहा है। जैसे अभी बताया था कि उसने चीन–पाक के बीच 'कारा–कोरम' हाईवे बना रखा है। पाकिस्तान ने अभी उसी कारा–कोरम हाईवे से चीन को चार लिंक रोड़ दिये है और उसने पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान में 'ग्वाडर' नामक स्थान पर 'नेवल बेस' अर्थात नौ सैनिक अड्डा बना लिया है। वहां से वह पूरी फारस की खाड़ी और हिन्द महासागर में अपनी नौ सैनिक उपस्थिति बढ़ा रहा है वहां से वह पूरी खनिज तेल परिवहन मार्ग पर अपना अंकुश रख सकेगा।

दूसरी तरफ, म्यानमार के साथ इसकी सीमा लगती है, उसके पूरे 'रीवर सिस्टम' को उसने नियन्त्रित कर रखा है। अन्दर बड़ी मात्रा में रोड़ तथा रेल लाइन का नेटवर्क बनाया है और अब सीधा वह बंगाल की खाड़ी में भी आ गया है। इसय तरह दोनो और से भारत की घेराबन्दी और इधर, बांग्लादेश के चटगांव में अपना 'नेवल बेस' बनाया है और अण्डमान द्वीप के पास में बर्मा के 'कोको द्वीप' पर पूरा 'सर्विलेंस सिस्टम' सैन्य निगरानी तंत्र बना दिया है। वहाँ रडार स्थापित कर चीन ने भारत के पूर्वी तट की पूरी निगरानी करनी प्रारम्भ कर दी है।

अभी इन्टरनेट के क्षेत्र में 1 लाख नये साइबर यौद्धा (Cyber warriers) तैयार किये है। इन 1 लाख साइबर वारियर्स के माध्यम से वह विश्व भर में अन्य देशों के इण्टरनेट नेटवर्क में सेंध लगाता है। उसके सायबर वारियर्स महत्वपूर्ण साइट्स हैक करते है और महत्वपूर्ण सूचनाऐं प्राप्त करते है।

तीन–चार वर्ष पूर्व अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास की, महत्वपूर्ण साइट हैकर की चपेट में आई और सारी सूचनाऐं साफ कर ली गई। इस प्रकार चीन द्वारा सभी मोर्चों पर भारत पर दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका के लाकहीड मार्टिन व उसकी सहयोगी कम्पनियों के इण्टरनेट तंत्र में जाकर अमेरिका के पाँचवी पीढ़ी के युद्धक विमानों के ब्लूप्रिण्ट भी इन्ही साइबर योद्धाओं ने चुरा लिये, ऐसा भी आरोप अमेरिका लगा रहा है। हमारे रक्षा विभाग व अनुसन्धान प्रयोगशालाओं की भी अनेक सूचनाएँ ये साइबर वारियर्स हड़प कर ले जा रहे है। हमारे इण्टरनेट सूचना तंत्र की सुरक्षा व कोई कमान प्रणाली नहीं होने से वह हमारी और भी सूचनाएँ ले जा सकता है। उत्तर भारत के 2012 के ग्रिड फेल्यर जैसे, और हमारे रक्षा इन्टरनेट सूचना तंत्र को विफल करने जैसे कई कारनामे वह कर सकता है। आज देश में सर्वाधिक टेलीफोन एक्सचेंज व इलेक्ट्रॉनिक संचार सामग्री चीनी है। सर्वाधिक पर्सनल कम्प्यूटर (PC) चीनी 'लीनोवो' बिक रहे हैं। उनके माध्यम से हम पर कोई भी साइबर आक्रमण करना उसके लिये अत्यन्त सहज होगा। 4132 उसने अभी सीमा क्षेत्र में लगभग पूरी सीमा पर, उसकी आऊट–पोस्ट, जो काफी पीछे होती थी, सीमा से, उन सब आऊट–पोस्ट को सीमा पर ले आया है, लगभग वैसी ही स्थिति में, ले आया है जैसी 1950 में उसने चौकसी बढ़ाई थी, ठीक वैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है, तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने पण्डित नेहरू को पत्र भी लिखा था और गृहमंत्री के नाते कई स्थानों पर पुलिस चोकियाँ, उन्होनें स्थापित की थी। उन्ही पुलिस चौकियों के कारण ही हमें 1962 में चीन के, वहां आने की जानकारी मिल पाई थी। उस समय भी, उसका, अभी जैसे, सरकार ने स्वीकार किया है और रिकॉर्ड पर है कि उसने लेह–लदाख में तो कुछ समय पूर्व ही 1.5 किलोमीटर तक उसकी सेना घुस आई और चट्टानों पर 'चाईना' लिख दिया। उसकी घुसपेठ की जो रणनीति है, वही है जो 1962 के आक्रमण से पहले अपनाई थी।

चीनी सैनिकों का बार–बार आना और तत्काल चले जाना, जिससे हमारी सैना और सरकार को यह लगता है कि ये तो आते है, चले जाते है, कोई खास बात नहीं है और जब हम असावधान हो जाते है। तब वे आते है और वहीं जम जाते है और वापिस नहीं जाते है। अक्साई–चिन पर जो कब्जा किया उसकी रणनीति यही रही थी। चीन वहां बार–बार घुसपेट करता रहा, आता रहा, जाता रहा, वहाँ सड़क बना ली और फिर उसने भांप लिया कि हम असावधान है, तो कब्जा कर लिया और जब हमने अपना ट्रूप–मूवमेन्ट शुरू किया तो कुछ क्षेत्रों में पीछे भी हट गया। दूसरी ओर, आज चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मोड़ने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मपुत्र सहित तिब्बत से 10 बड़ी नदियाँ निकलती हैं और जिनसे 11 देशों को जलापूर्ति होती है, चीन उन नदियों के जल को मन चाहे ढंग से मोड़ रहा है। यदि तिब्बत पर चीन का अधिकार नहीं होने दिया होता तो यह जल संकट नहीं उपजता।

अध्याय 4

चीन के सन्दर्भ मे प्रभावी रीति–नीति आवश्यक

चीन के बढ़ते भू राजनैतिक, आर्थिक व तकनीकी वर्चस्व, सीमा पर बढ़ते दबाव एवं देश के अन्दर बढ़ते चीनी कम्पनियों के जाल के आलोक में भारत को प्रभावी प्रतिकार की रीति–नीति विकसित करनी चाहिये। चीन ने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अमेरिका को पीछे छोड़कर क्रमांक एक पर आने के लिये सशक्त पहल की है। इस दृष्टि से भी हमको उपयुक्त व्यूह रचना पर विचार करना होगा।

सर्वप्रथम भारत–तिब्बत सीमा रक्षा व प्रबन्ध गृह मंत्रालय से लेकर, तत्काल सेना को सौंप देना चाहिये। इस हेतु भारत–तिब्बत सीमा पुलिस का संचालकीय नियन्त्रण सेना को दे देना चाहिये। भारत–पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल व बाँग्ला सीमा पर आसाम राइफल्स पर भी नियन्त्रण सेना का ही है। तब फिर भारत–चीन सीमा, जहाँ अधिक तनाव है, वहाँ पर गृह मंत्रालय का क्या औचित्य है?

हमारी रक्षा तैयारियाँ, चीन व पाक से बेहतर होनी चाहिये। आज हमारी 1.06 लाख वर्ग किमी. भूमि पर पाक व चीन ने अतिक्रमण कर रखा है। उसे मुक्त कराने के लिये हमें सशक्त बनना होगा। शेष सीमावर्ती क्षेत्र में भी चीन की बार–बार की घुसपैठ रोकने के लिये भी सीमा पर अवसंरचना विकास, पर्याप्त सैन्य बल की तैनातगी एवं उन्नत शस्त्रास्त्रों का विकास कर उनको सेना में सम्मिलित करना भी आज की अनिवार्य आवश्यकता है। चीन के पास 6 नाभिकीय पनडुब्बियाँ जहाज भेदी प्रक्षेपास्त्र, उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र, एक से अधिक नाभिकीय बम ले जाने वाले इण्टरकाण्टिनेण्टल बैलिस्टिक मिसाइलें आदि हैं। उनके प्रतिकार की हमारी तैयारी आवश्यक है। चीन (J-20 व J-31) दो पाँचवी पीढ़ी के ऐसे युद्धक विमानों का परीक्षण कर चुका है, जो रडार से नहीं देखे जा सकते हैं (Fifth Generation Stealth Fighter Aircraft) चीन अपने विमानकारी जहाजों पर भी पाँचवी पीढ़ी के J-31 को तैनात कर रहा है। भारत अभी तीसरी पीढ़ी के तेजस पर ही काम कर रहा है और राफेल्स जो खरीद रहा है, वहीं भी पाँचवी पीढ़ी का नहीं है। इस दिशा में भी हमारी प्रभावी पहल होनी चाहिये।

दौलत बेग ऑल्डी, चूमार व सिटी जेप सहित लद्दाख के सभी सीमावर्ती क्षेत्र में समुचित सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिये। अतएव देश को अपना रक्षा व्यय बढ़ाना चाहिये। वर्तमान में हुये दौलत बेग ओल्डी जैसे अतिक्रमणों का तत्काल सैन्य प्रत्युत्तर देकर, घुसपैठ करने वाले सैन्य बल को बलपूर्वक निकाल बाहर करने की नीति निर्धारित करनी चाहिये।

चीन ने सभी क्षेत्रों में अपनी टेक्नोलॉजी के समुन्नयन के लिए 1.5 ट्रिलीयन डॉलर (75 लाख करोड़ रूपये, जो आज हमारे देश के जी.डी.पी. के बराबर है) का अनुसन्धान व विकास (आर एण्ड डी) के लिये प्रावधान किया है जिससे वह प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अमेरिका से आगे निकले। इसलिए भारत को चीन की इस सम्पूर्ण बढ़त को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। दूरसंचार के क्षेत्र में पाँचवी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा में आगे बढ़े इससे पूर्व हमें 2G, 3G, व 4G प्रौद्योगिकी समुन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। और पाँचवी पीढ़ी की दूर संचार प्रौद्योगिकी के विकास की पहल करनी चाहिये।

इसके साथ ही हमें तत्काल पहल करते हुये सबसे पहले तो चीन के उत्पादों का सम्पूर्ण बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिये। उसके लैम्प, खिलौने, मोबाइल फोन से लेकर, उसके कम्प्यूटर पर्यन्त जितनी आम उपभोक्ता चीजे खरीदते उनके ऊपर हम अंकुश लगा ही सकते है, साथ ही यदि जन चर्चाओं, सार्वजनिक कार्यक्रमों और व्यक्तिगत बातचीत, साक्षात्कार आदि में लोगों को चीन के इन खतरो के प्रति आगाह करते हैं, तब एक ऐसा वातावरण बनेगा कि सरकार चीनी कम्पनियों को जो नई–नई सुविधाएं दे रही है, बन्द करने को बाध्य होगी। एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि चीन चाहे डब्ल्यू टी ओ का मेम्बर है तब भी चीन नॉन मार्केट इकोनॉमी है। बाजार आधारित अर्थ व्यवस्था नहीं है। हमने उसको नॉन मार्केट इकोनॉमी की केटेगरी में रख रखा है। इसलिए डब्ल्यू टी ओ के अन्तर्गत दूसरे देशों को जो व्यापार व निवेश की सुविधाएँ देते हैं वे चीन को देना हमारे लिए कतई आवश्यक नहीं है। इसलिए आसानी से सरकार चीनी कम्पनियों की हमारे देश में बढ़त को रोकने का अधिकार रखती है। केवल नैतिक बल व राजनीतिक साहस चाहिये जो जनमत के दबाव से ही सम्भव है।

चीन के कर्मचारी और टैक्नोक्रेट्स, जो अवैधानिक रूप से देश में रह रहे है, उनको गिरफ्तार करके डीपॉर्ट करना तो सरकार का दायित्व है। चीनी कम्पनियों को बड़ी मात्रा में जो परियोजनाएँ दी जा रहीं हैं उन पर तो अंकुश लगाया ही जाना चाहिये। इन्टरनेट पर फेस बुक से लेकर सभी प्रकार के सोशल नेटवर्क्स हैं, उनके माध्यम से चीन के द्वारा जो मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, और अबोध रूप से जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उसके आलोक में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आव्हान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है।

यह चीन को अपने वैश्विक व मानवोचित दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनायेगा। चीन ने तो आज एक लाख साईबर योद्धा नियुक्त कर रखे हैं जो इन्टरनेट पर जाते है और हमारी सुरक्षा सम्बन्धी व अन्य संवेदनशील सूचनाएँ हड़प कर ले जाते है। हमारे रक्षा मंत्रालय के कम्प्यूटर सिस्टम से भी बड़ी मात्रा में सूचनाएँ उसने चुराई हैं। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास के कम्प्यूटर से सारी की सारी संवेदनशील जानकारियां चीन के साईबर योद्धा चुराकर ले गये हैं। जिस प्रकार का साईबर युद्ध चीन ने भारत के विरूद्ध छेड़ रखा है, हमें भी वैसा ही साईबर युद्ध और चीनी उत्पादों में

बहिष्कार का अभियान छेड़ना चाहिये। चीन का आज जो कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) है, उसका 60 प्रतिशत निर्यात आधारित है। अगर चीन के उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो में खपत बन्द हो जाती है तो उसके सारे के सारे कारखाने तीन गुनी ओवर कैपेसीटी के शिकार होकर बन्द होंगे और वहां के बैंका के ऋण डूबने का शिकार होकर, उसकी अर्थ व्यवस्था चौपट हो सकती है। 2008 की जो आर्थिक मंदी थी, उस आर्थिक मंदी के दौर में चीनी अर्थ व्यवस्था बिल्कुल धूल धूसरित होने की स्थिति में आ गई थी। चीन के बैंको को 1.2 ट्रिलीयन डॉलर (60 लाख करोड़ रूपये) के कर्जे बांटने पड़े थे, ताकि लोगो की घरेलू खपत बढ़े और उसके कारखाने चालू रह सकें और वह बेरोजगारी, मंदी व उद्यम बन्दी का शिकार न हो। उन ऋणों में से आज 400 अरब डॉलर के ऋण नान परफार्मिंग एसेट (डूबते हुए कर्जो) में बदल गये हैं। चीन के बैंकों के कुल ऋणों का अनुमानतः 17 प्रतिशत आज नान परफोर्मिंग एसेट की श्रेणी में हैं। हमारे देश में यह ऋण दो प्रतिशत से कम है। इसलिये दीर्घकालिक दृष्टि से चीन की अर्थ व्यवस्था की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था इस दृष्टि से सुदृढ़ है। बस, यह 'बहिष्कार अभियान' ही भारत को क्रमांक एक की आर्थिक शक्ति बनायेगा। आज चीन और भारत को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत विश्व की खाद्य शक्ति की सामर्थ्य रखता है। हमारे पास साढ़े सोलह करोड़ हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। चीन के पास 9 करोड़ हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि ही है। उसके पास 11 करोड़ हैक्टेयर कृषि युक्त भूमि थी लेकिन इन्फॉस्ट्रक्चर डवलपमेन्ट के चक्कर में उसकी 2 करोड़ हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि नष्ट हो गई और वह खेती करने के योग्य नहीं रही। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत आज विश्व में क्रमांक एक पर है। भारत जितनी (5 करोड़ 70 लाख हैक्टेयर) सिंचित कृषि योग्य भूमि किसी भी देश के पास नही है। चीन भी दूसरे स्थान पर है। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से आज भी भारत कई क्षेत्रों में चीन की तुलना में बेहतर स्थिति रखता है। चीन के प्रोडक्ट्स, आज हम भी अपने देश में देखते है कि, टिकाऊ नहीं है। इस प्रकार चाहे हमारी प्रौद्योगिकी हो, या कृषि सामर्थ्य अथवा चाहे हमारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव हो या विश्वसनीयता, भारत की अपनी एक छवि है।

भारत को विश्व के अधिकांश देश एक विश्वसनीय सत्ता के रूप में देखते हैं। चीन को एक निरंकुश शक्ति के रूप में आँकते हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध जगत में भारत अच्छा प्रभाव बना सकता है। चीन के इन वक्तव्यों कि ''बौद्ध पंथ की विरासत चीन के पास है न कि भारत के पास'' को बौद्ध जगत गम्भीरता से नहीं लेता है। आज बौद्ध जगत के साथ अपने सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने की बात हो या साईबर युद्ध, चीन के उत्पादों के बहिष्कार से चीनी विकास को शिथिल करना हो अथवा चाहे हमारी प्रौद्योगिकी का जो स्तर है, और हमारी जो कृषि सामर्थ्य है, उस सब दृष्टि से भारत आज बहुत द्रुत गति से चीन से आगे बढ़ने की स्थिति में है। चीन में आने वाले समय में वृद्धों के बढ़ते अनुपात का संकट आने वाला है। वहाँ प्रति एक कार्यशील व्यक्ति पर 6 वृद्धों का जो अनुपात होगा वह भी उनके विकास में बाधक सिद्ध होगा। दूसरी ओर 2020 तक दुनिया की 28 प्रतिशत श्रम शक्ति भारत के पास होगी। विश्व के सारे ज्ञान आधारित क्षेत्रों में भारतीय होंगे। ऐसे में हमको चीन के उपभोक्ता उत्पादों की जो भारत में बाढ़ आई हुई है, हमारे देश में सारी निर्माण परियोजनाओं से लेकर टेलिफोन, विद्युत संयन्त्र स्थापना के कार्य जो चीन को दिये जा रहे हैं और चीन के उत्पादों की जो विश्व में बिक्री हो रही है, विश्व बाजारों में यदि मानवाधिकारों के हनन व पर्यावरण क्षरण आदि के आधार पर चीनी उत्पादों का बहिष्कार होता है, जिसकी पहल हम कर सकते हैं तो शायद एक या दो वर्ष में ही चीन की अर्थ व्यवस्था अपने ही बोझ के तले दबकर पिछड़ सकती है। आज उसके सकल घरेलू अनुपात में 60 प्रतिशत निर्यातों का अनुपात है। उसकी अत्यधिक निर्यात निर्भरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सिद्ध होगा। चीन उत्पादों को यदि भारतीय उत्पाद प्रतिस्थापित करते हैं, तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन से अधिक व विश्व में सर्वोच्च हो सकती है। इसलिये यदि भारत में चीन निर्मित वस्तुओं का उपयोग बन्द होता है तो चीन को, भारत से जो 3 से 4 लाख करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा व चीन की सरकार को 35 से 40 हजार करोड़ रूपयों का कर राजस्व (टेक्स की आय) मिल रहा है, उसमें कमी आयेगी और देश का धन देश में रहेगा। यदि भारत सरकार पर चीन के विरूद्ध प्रभावी जन दबाव बनता है, तो सरकार चीन के देने वाली व्यापारिक सुविधाओं में कटौती के लिये बाध्य होगी और सीमा विवाद पर भी कठोर रूख अपनायेगी। इसके साथ ही यदि चीन द्वारा किये जा रहे मानवाधिकारों के हनन, तिब्बती जनता के दमन और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबन्धों की अवहेलना कर कई देशों में जन आन्दोलनों को कुचलने हेतु छोटे हथियारों की आपूर्त्ति और पर्यावरण को विनष्ट करने में अग्रणी होने के तथ्य इण्टरनेट आदि के माध्यम से विश्व जन समुदाय में प्रसारित होते है। तो चीन निर्मित वस्तुओं का उपभोग सम्पूर्ण विश्व में घटेगा। चीन भारत के निर्यात बाजारों पर कब्जा करने में सफल नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त चीन की अर्थव्यवस्था निर्यातों पर अवलम्बित है। उसके गैर कृषि क्षेत्र का लगभग दो तिहाई उत्पादन निर्यात आधारित है। यदि चीन के निर्यात घटते हैं और उसकी आर्थिक वृद्धि दर में कमी आती है, तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर दो क्रमांक से एक पर पहुंच जाएगी। चीनी आर्थिक वृद्धि दर नियन्त्रण में रहेगी तो उसकी सामरिक बढ़त व महात्वाकांक्षाएँ भी सीमा मे रहेंगी। अस्तू देश, समाज व विश्व–मानवता के प्रति संवेदनशील जन–मानस को चीन की बढ़त को नियंत्रित रखने हेतु सक्रियता दिखलानी चाहिये। विश्व–मानवता के हितार्थ भारत को अपने वैश्विक दायित्व निर्वहन हेतु आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में विश्व नेतृत्व के अपने वैश्विक दायित्व के प्रति सजगता बढ़ानी होगी।

संक्षेप में देशवासियों को चीन में बनी वस्तुओं का सम्पूर्ण बहिष्कार करना चाहिये। सरकार पर भी इस बात के लिये दबाव बनाना चाहिये कि वह चीनी आयातों को नियंत्रित करे और चीनी कम्पनियों को देश की परियोजनाओं में काम नहीं दे। भारत–तिब्बत सीमा पर नियन्त्रण गृह मंत्रालय के स्थान पर सेना को सौंप दिया जाना चाहिये। चीन की सामरिक सामर्थ्य से बेहतर रक्षा सामर्थ्य विकसित करना आवश्यक है। विदेश नीति को प्रभावशाली बनाते हुये भारत के मित्र देशों पर बढ़ते चीनी प्रभाव को परिमित करने की पहल करनी चाहिये। उन सभी देशवासियों को इंटरनेट व सोशल मीडिया पर, चीनी उत्पादों के वैश्विक बहिष्कार का वातावरण बनाना चाहिये, जो इन साधनों का उपयोग करते हैं। चीन द्वारा किये जा रहे मानवाधिकारों के हनन व विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने के प्रवृत्ति को देखते हुये इसमें अत्यन्त अच्छी सफलता मिलेगी। चीनी अर्थव्यवस्था उसके निर्यातों पर अवलम्बित होने से आर्थिक बहिष्कार से उसका पराभव अवश्यम्भावी है।

सारांश

इस प्रकार चीन की कुटिलताओं पर दृष्टिपात करे तो, उसकी अनगिनत शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां है। इनका संक्षिप्त पुरावलोकन निम्नांकित बिन्दुओं में संभव है।

- 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर 38000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इसके बाद 1963 में हमारे शत्रु पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर की 5183 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन को दे दी। अब चीन सम्पूर्ण पाक अधिकृत कश्मीर में व्यापक गतिविधियाँ संचालित कर रहा है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का 68 हजार वर्ग किमी. वाले भू–भाग में आज चीन अनेक प्रकार के सैन्य निर्माण कर रहा है। वहाँ से वह अपने राजमार्ग निकाल रहा है। भारत के कठोर विरोध के उपरान्त पर भी चीन वहाँ अपनी उपस्थिति बढ़ाता ही जा रहा है। वहीं से वह 46 अरब डालर के निवेश वाला चीन पाक आर्थिक गलियारा भी निकाल रहा है।
- भारत के आर्थिक हितों को हानि पहुंचाने के लिए चीन ने अफ्रीका में 'मेड इन इण्डिया' ब्राण्ड की वस्तुएं विशेष कर दवाईयाँ भी प्रवेश कराने का दुस्साहस किया था। इसका स्पष्ट उद्देश्य अफ्रीका में भारतीय वस्तुओं को बदनाम करना था।
- पाँच वर्ष पूर्व चीन ने भारत के सूती वस्त्र उद्योग को चौपट करने के लिए देश में उत्पन्न अधिकांश कपास को अत्यन्त ऊँचे दाम पर खरीद लिया था। जब देश में कपास का मूल्य 4000/– रूपये क्विटल था तब उसने 7000/– रूपये प्रति क्विंटल खरीद कर भारतीय वस्त्र उद्योग को चौपट करने का प्रयत्न किया था।
- आज देश में अनेक उद्योग चीन से बढ़ रहे आयातों के कारण बन्द हो चुके है और बड़ी संख्या में और भी उद्योग बन्द होने को है। इनमें विद्युत साज सामान, बल्ब उद्योग, टायर उद्योग, मोबाईल फोन, स्मार्टफोन उद्योग, इलेक्ट्रोनिक साजसामान के उद्योग, कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग पेन आदि स्टेशनरी सामानों के उद्योग, खिलौना उद्योग, औषधी उत्पादन उद्योग आदि है।
- चीन आज अरूणाचल प्रदेश सहित देश की 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अपना दावा जता कर सीमा चौकियाँ आगे बढ़ाते हुए घुसपैठ करके हमारे निर्माण कार्यों में बाधा डाल रहा है। हर वर्ष वह 400 तक सीमा का अतिक्रमण करता है और सीमावर्ती गांवों के निवासियों को आतंकित कर वहाँ अपने अस्थायी कैंप स्थापित देता।
- चीन द्वारा जम्मू–कश्मीर को अपने नक्शों में भारत का अंग नहीं दिखाया जाता है। अरूणाचल प्रदेश को चीन का अंग दिखाकर वहाँ के नागरिकों को बिना पासपोर्ट वीजा के चीन आने का आमन्त्रण दिया जाता है।
- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा अरूणाचल को ''हमारा सूरज का प्रदेश'' कहने पर चीन हमारी महिला राजदूत को रात्रि 2 बजे उठाकर कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए चेतावनी देता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अरूणाचल प्रदेश के तवांग जिले में प्रवेश नहीं करने की धमकी देता है और मनमोहन सिंह वहां की यात्रा निरस्त कर देते हैं।
- चीन ने आणविक आपूर्ति समूह (Nuclear Supplier Group) में भारत के प्रवेश पर आपत्ति करते हुए यह शर्त लगा दी है कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को जबतक इस समूह में प्रवेश नहीं मिलेगा तब तक वह भारत को भी इसमें प्रवेश नहीं लेने देगा।
- चीन ने हमें आहत करने हेतु लश्कर–ए–तोयबा के आतंकवादी व जैश–ए–मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत भारत के प्रस्ताव सहित 2009 से अनेक बार वीटो उपयोग कर भारत का विरोध किया।
- भारत की उड़ी में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के विरूद्ध सैन्य कार्यवाही के विरोध में पाकिस्तान के प्रति अपनी मित्रता का प्रदर्शन करते हुये चीन ने जेंगबो नामक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी अवरूद्ध कर भारत को परोक्ष में यह चेतावनी दी है कि भारत द्वारा पाकिस्तान के विरूद्ध आतंकवाद विरोधी कार्यवाही करने और पाकिस्तान को सिन्धु नदी के जल से वंचित करने पर वह ब्रह्मपुत्र नदी के जल से भारत को वंचित कर देगा। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की उपरोक्त सहायक नदी का पानी रोकने के लिये ही वहाँ एक हाईड्रो प्रोजेक्ट लगा रहा है। भारत क लिए यह भारी चिंता की बात है क्योंकि चीन के इस कदम से भारत समेत कई देशों में ब्रह्मपुत्र के पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है। इससे भारत की 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।
- चीन ने यह काम ऐसे वक्त में किया है जब उड़ी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सिन्धुजल समझौते के तहत होने वाली बैठक रद्द कर दी थी। साथ ही इस समझौते की समीक्षा करने का भी फैसला किया था। भारत ने यह निर्णय पाक पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के विरूद्ध दबाव बनाने के लिए किया था। ऐसे में चीन का यह कदम पाकिस्तान के साथ मिलकर उल्टा भारत पर दबाव बढ़ाने की धमकी के रूप में उपयोग कर रहा है। तिब्बत में यारलुंग जेंगबो नाम से जानी जाने वाली ब्रम्हपुत्र की एक सहायक नदी पर चीन ने इस प्रोजेक्ट पर करीब 750 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया है। यह प्रोजेक्ट तिब्बत के जाइगस में है। यह जगह सिक्किम के नजदीक पड़ती है। जाइगस से ही ब्रह्मपुत्र नदी अरूणाचल प्रदेश में बहते हुए दाखिल होती है।
- चीन अपने इस अत्यन्त महंगें प्रोजेक्ट को 2019 में पूरा कर लेना चाहता है। यह पानी रोकने से भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में ब्रह्मपुत्र के बहाव पर व्यापक असर पड़ेगा पिछले वर्ष भी चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र में डेढ़ बिलियन की लागत वाला सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट शुरू

किया था। इस पर भी भारत ने चिंता जताई थी। लेकिन, चीन ने इसकी अनदेखी कर दी है। चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना से इस बात के संकेत मिलते हैं कि तिब्बत के स्वायत क्षेत्र में चीन तीन और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट केवल भारत का जल हड़पने के लिये लाने वाला है। इससे सम्पूर्ण पूर्वोत्तर में गम्भीर जल संकट पैदा होगा और चीन इन बांधों का पानी कभी भी छोड़कर पूर्वोत्तर में जलप्लावन का संकट खड़ा कर सकता है।

- चीन वर्ष में 300–450 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करता है।
- चीन ने भारतीय सीमा पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है जिनके मारक क्षेत्र में सम्पूर्ण भारत आता है।
- भारत की चारों ओर से घेराबन्दी की दृष्टि से चीन ने पाकिस्तान (ग्वादर बंदरगाह), नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश (चटगांव बंदरगाह) एवं श्रीलंका में सैन्य गतिविधियों का विस्तार किया।
- हमारे देश के अतिसंवेदनशील स्थानों पर विविध परियोजनाओं में निर्माण के ठेके अत्यन्त कम दरों पर भरकर देश के अन्दर चीन अपनी उपस्थिति एवं गतिविधियाँ बढ़ा रहा है।
- चीन ने दैनिक उपयोग की लगभग प्रत्येक घटिया वस्तु को भारत के बाजारों में सस्ते मूल्य में पहुंचा कर स्थानीय उद्योगों को बन्द कराने की स्थिति में पहुंचा दिया है। चीन से भारत को आयात लगभग 4.5 लाख करोड़ रूपये वार्षिक तो घोषित है और बिना बिल का या अल्प मूल्य के बिल से आ रहे सामान को जोड़ देवें तो यह राशि 7 लाख करोड़ रूपये वार्षिक तक पहुँच सकती है। क्या हमें चीन जैसे हमारे साथ शत्रुतापूर्ण कार्यवाही करने वाले देश का इतना माल खरीद कर उसका 6–7 लाख करोड़ का आर्थिक सशक्तिकरण करना चाहिये? यदि इस पर न्यूनतम 10 प्रतिशत भी कर (टेक्स) की राशि चीन की सरकार को जाती है तो हम भारत में रहते हुये अपने शत्रु देश की सरकार को 60–70 हजार करोड़ रूपये की कर अर्थात टेक्स की आय में योगदान दे रहे हैं इसलिये हमें तत्काल ही चीनी वस्तुओं का क्रय करना बन्द करना चाहिये। आज हमारे लिये राजस्व संकट के चलते थल सेना के बारम्बार आग्रह के बाद भी भारत को भारत–तिब्बत सीमा के लिये पर्वतीय आक्रामक सेना को शस्त्र सज्जित करने में कठिनाई आ रही है। यदि चीनी माल खरीदना बन्द कर दे तो ये 60–70 हजार करोड़ रूपये चीनी सरकार के हाथ पड़ने से रूक सकेंगे। दूसरी ओर यही माल भारत में निर्मित होकर इस माल को हम भारतीय खरीदेंगे तो देश की सरकार को इस माल का 16 प्रतिशत की दर से 1 लाख करोड़ से अधिक का कर राजस्व मिलेगा। हमारे लिये पर्वतीय आक्रामक सेना के लिये कुल ही 60,000 करोड़ रूपये मात्र की और आवश्यकता है।
- चीन का रक्षा बजट 200 अरब डालर है जबकि भारत का रक्षा बजट मात्र 40 अरब डालर है। इसे हम भारतीय माल खरीद कर अपना कर राजस्व बढ़ा कर ही बढ़ा सकेंगे।
- 14 अप्रैल, 2013 की रात्रि में बिना टेंकों या तोपखाने के 40 चीनी सैनिकों ने हमारी सीमा में 19 किमी. तक घुसपैठ कर दौलत बेग ओल्डी में तम्बू गाड़ दिये। भारत सरकार उन्हें बाहर धकेलने के स्थान पर उनसे ब्लेकमेल होती चली गयी और उन्हें बाहर जाने को मनाने के लिये हमारे द्वारा अपनी ही सीमा में अपनी सेना को सीमा में 38 किमी. पीछे ले जाना पड़ा और हमारी सीमा में अपनी रक्षा संरचनाएँ यथा सेना के बंकर आदि अपने ही हाथों से तोड़ने पड़े थे।

इसलिए आज हम संकल्प ले कि चाहे हमें किसी भी वस्तु के उपभोग से वंचित रहना पड़े तो भी कोई चीनी उत्पाद नहीं खरीदेंगे। समाज में भी अभियान चला कर सभी देशवासियों से आग्रह करें कि वे भी कोई चीनी सामान नहीं खरीदें। आजकल चीन कई वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही कर रहा है। इसलिए उन पर 'मेड इन इण्डिया' भी लिखा होता है। इसलिए चीनी ब्राण्डों की पहचान करने हेतु कुछ चीन के सामानों व मोबाइल फोनों के ब्राण्डों के नाम यहाँ दिए जा रहे है। लेनोवा, ओपो, हुवाई, क्जिोमी, एमआई 4, एल्काटेल, अमोई, बीबीके, कूलपेड, कबोट, जी 5, जियोनी, हेयर, हिसेन्स, कोन्का, मोटा, जेडटीई, लिईको, मैजु, वनप्लस, क्हु 360 आदि इसलिए इन ब्राण्डों एवं अन्य भी चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। अंग्रेजी में इन ब्राण्डों की स्पेलिंग अग्रानुसार है – Lenovo, Oppo, Huawei, Xiomi, mi4, Alcatel, Amoi, BBK, Coolpad, Cubot, Gfive, Gionee, Haier, Hisense, Konka, Motto, ZTE, LeEco, Meizu, OnePlus, Qihoo360, QiKU, Ningbo Bird, Smartisan, Technology Happy Life, Vivo, Vsun, Wasam, Xiomi, Zopo Mobile, Zuk Mobile.

समाधान :

उपरोक्त सभी शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां का उत्तर चीनी वस्तुओं के बहिस्कार से ही दिया जा सकता है। इस संबंध में निम्न कार्य विशेष रूप से हमें करने हैं –

1. चीनी वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार।
2. सभी व्यापारियों एवं उद्यमियों से भी चीनी वस्तुओं को आयात नहीं करने का आग्रह करना।
3. चीनी वस्तुओं पर तकनीकि आधार पर यथा सम्भव रोक लगाने के लिए सरकार से आग्रह करना।
4. चीन को स्पष्ट चेतावनी देना कि उसके द्वारा विविध अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध जारी रहा और उसके द्वारा सीमा का अतिक्रमण भी जारी रहेगा तो भारत सरकार चीन से आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देगी।
5. यदि तब भी चीन की सरकार नहीं माने तो पहले सीमित अवधि के लिए और बाद में पूरी तरीके से चीनी आयात पर प्रतिबन्ध लगा देना। चीन

को स्पष्ट चेतावनी देना कि यदि उसने भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई तो भारत के लोग सोशल मिडिया पर सम्पूर्ण विश्व समुदाय पर चीनी उत्पाद का बहिष्कार करने का आग्रह करेंगे।

6. चीन द्वारा जिस प्रकार से विश्व के अनेक भागों में मानवाधिकार के हनन में लिप्त है। तिब्बत में भी व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का हनन किया है इसके साथ ही उसने पर्यावरण विनाश की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कर रहा है।

7. चीन के इन सभी दुष्कृत्यों का ठीक–ठाक प्रसार करने पर सम्पूर्ण विश्व में चीनी वस्तुओं का बहिस्कार प्रारम्भ हो जायेगा और इससे ही चीन सही मार्ग पर ठिकाने पर आएगा।

लेखक द्वारा लिखित स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर स्तरीय पाठ्यपुस्तकें

1) प्रबंध
2) प्रबन्ध व संगठन व्यवहार
2) व्यावसायिक सन्नियम
3) प्रतिभूति विनियम एवं वित्तीय बाजार
4) कंपनी अधिनियम
5) व्यावसायिक वातावरण
6) उद्यमिता
7) अन्तर्राष्ट्रीय विपणन
8) व्यावसायिक संचार
9) विक्रय प्रबंध
10) औद्योगिक एवं व्यापारिक सन्नियम

लेखक परिचय

प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा
पीएच.डी., एम.कॉम

प्रो. शर्मा 1978 से वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकायों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन कर रहे हैं। आपने वाणिज्य एवं प्रबन्ध के क्षेत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिये 11 पुस्तकें लिखी हैं जो हिमालय पब्लिकेशन आदि राष्ट्रीय स्तर के ख्यातनाम प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गयी हैं। इनके मार्गदर्शन में 15 छात्रों ने पीएच.डी. स्तर का शोध किया है एवं इन्होने 80 से अधिक अन्य शोध परियोजनाओं का निर्देशन किया है। विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में इनके 70 से अधिक लेख एवं शोध पत्र प्रकाशित हुये हैं।

आर्थिक एवं वैश्विक व्यापार सम्बन्धी विषयों में रुचि होने से प्रो. शर्मा ने स्वदेशी जागरण मंच की ओर से, विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) के पाँचवे एवं छठे मंत्रिस्तरीय द्विवार्षिक सम्मेलन में 2003 में केन्कुन (मैक्सिको) व 2005 में हाँगकाँग में भाग लिया हैं।

प्रबन्ध के क्षेत्र में प्रो. शर्मा अन्तर्व्यक्ति व्यवहार की प्रभावशीलता, समय प्रबन्धन, संगठन विकास, शून्य आधारित बजट परिवर्तनों के प्रबन्ध, नेतृत्व विकास आदि विषयों के प्रशिक्षक भी हैं।

इन्होंने आर्थिक वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, स्वदेशी, विनिवेश आदि विषयों पर 10 लघु पुस्तिकाएँ भी लिखी हैं। वर्तमान में प्रो. शर्मा स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक भी हैं।

इनका ई–मेल आई. डी. bpsharma131@yahoo.co.in है।

View publication stats